THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): If any clarification is needed, we can fix a time for that.

SHRI ARUN JAITLEY: I have no difficulty in fixing a time. Whatever time is convenient to the hon. Finance Minister, may be fixed. This statement was read to us even in the morning by the hon. Home Minister. The queries are completely beyond the scope of the statement. Therefore, either we can make them today or the Finance Minister can go through the proceedings of today morning and whatever time is convenient to him, we can then put our queries.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I will go through the proceedings of the House and thereafter we will fix up a day mutually convenient to us.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, that is over. ...*(Interruptions)*... That is over.

DR. V. MAITREYAN: Sir, are we fixing it for 12 noon, on a day after tomorrow?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): That has already been said. It will be discussed with the LoP.

DR. V. MAITREYAN: We want some assurance from the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): The Finance Minister has said that it would be discussed with the LoP and then a decision would be taken.

DR. V. MAITREYAN: We are also part of it. We should also be there.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That means all are included. You are also included in that. Both the sides are included, this side and that side. Why do you doubt it? You are very much included. Who is excluding you? Don't think that anybody is excluding you. Now, Short Duration Discussion. Shri Shanta Kumar.

SHORT DURATION DISCUSSION

Problem of food grains storage in the country

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी बड़े-बड़े लोगों की, बड़ी-बड़ी कम्पनियों की, बड़ी-बड़ी बातों के बारे में बहुत गरम बहस हुई है। मैं इस देश के छोटे और गरीब आम व्यक्ति की एक समस्या सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष जी,

[श्री शान्ता कुमार]

अनाज भंडारण की समस्या गंभीर समस्या होती जा रही है। उसका प्रबंधन बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक तरफ किसान खून-पसीना लगाकर अनाज पैदा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उसको सम्भाल नहीं पा रही है। लाखों-करोड़ों रुपये का अनाज खराब हो रहा है। दुनिया में सब्जी, फल पैदा करने में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि लगभग 40, 50 हजार करोड़ रुपये की सब्जियां, फल आदि नष्ट हो जाते हैं, 80 हजार करोड़ रुपये का अनाज खराब हो जाता है। यह एक विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है।

दूसरी तरफ एक और दृश्य है। अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक चर्चा में कुछ शब्द कहे हैं, वे शब्द मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, "The Supreme Court has expressed its concern over unabated starvation deaths in the country and asked the Union and State Governemtns to ensure that no one should die due to hunger." फिर कहा है, "You can't have two Indians. What is this stark contradiction in our whole approach in eradication of malnutrition? You say you are a powerful country, but at the same time starvation deaths are taking place in various parts of the country." सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा। अखबारों में और भी खबरें रोज आ रही हैं कि कहीं पर कोई एक महिला अपने बच्चे को केवल एक हजार रुपये में बेचने पर मजबूर हो गई, कहीं पर कोई महिला, पदमा बेहरा केवल 7 हजार रुपये में अपने बच्चे को बेचने पर मजबूर हो जाती है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसकी ओर सरकार का ध्यान देना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आज देश के भण्डारों में 640 लाख टन अनाज है और इस साल 170 लाख टन और आने की सम्भावना है। कुल 810 लाख टन अनाज हो जाएगा और भण्डारण क्षमता केवल 460 लाख टन है। इसका मतलब कि 300 से लेकर 400 लाख टन अनाज बाहर रखा है, जो खराब होता है, बर्बाद होता है। यह स्थिति है। केवल अनाज रखने पर इस सरकार का 484 रुपए प्रति वर्ष क्विंटल खर्च आता है। यह सारी परिस्थिति जो आज है, जिसको बार-बार देखने की हमारी मजबूरी होती है, टीवी पर जब अन्न के भण्डार बर्बाद होते दिखाई देते हैं और जब अखबार में कहीं पर भुखमरी का समाचार आता है, तो किसी भी देशभक्त का सर शर्म से झुक जाता है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है।

मैं दो सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं और सरकार को बताना चाहता हूं। आप एकदम 400 लाख टन अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत पहले योजना बननी चाहिए थी, लेकिन आप तीन काम कर सकते हैं। मेरा पहला सुझाव है कि हम एक महीने का राशन करोड़ों लोगों को देते हैं, हम उन्हें ऑप्शन दें और उनको एक महीने के बजाए 6 महीने का अनाज देने की कोशिश करें। इसके लिए हम उन्हें एक इंसेंटिव दें, ताकि वे 6 महीने का राशन इकट्ठा कर लें। उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल इससे सरकार की भण्डारण क्षमता 175 लाख टन और बढ़ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि 60 हजार करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद होता है। मैं योजना आयोग की एक रिपोर्ट के कुछ शब्द पढ़ना

चाहूंगा। 'Report of Performance and Evaluation of PDS, March, 2005'. "Taken into account all the inefficiencies in the PDS, it is found that the Government of India spends Rs. 3.65 through Budgetary food subsidy to transfer Re.1 to the poor." गरीब आदमी को एक रुपया पहुंचाने के लिए यह सरकार 3 रुपए 65 पैसे खर्च कर रही है। जो भण्डारण किया जाता है, उसका खर्च 480 रुपए प्रति क्विंटल आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट अलग है। लेने में, ले जाने में, गोदाम तक पहुंचाने का खर्च अलग है। केवल गोदाम में रखने का खर्च 480 रुपए प्रति क्विंटल आता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप 6 महीने का राशन इकट्ठा देंगे, तो 6 महीने राशन रखने का आपका खर्च बच जाएगा। 6 महीने एक किलो राशन रखने पर आपका खर्च 2 रुपए 40 पैसे आता है। जब लोग 6 महीने के लिए अनाज ले जाएंगे, तो आपके 2 रुपए 40 पैसे बचेंगे। 40 पैसे सरकार अपने पास रखे और अनाज 2 रुपए किलो सस्ता कर दे। आज की कमरतोड़ महंगाई के जमाने में उन करोड़ों लोगों को अगर आप अनाज 2 रुपए किलो सस्ता देंगे, तो 6 महीने का अनाज उठ जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी कल हमने संसद के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया, सरकार यह घोषणा करे कि हम उसी उपलक्ष्य में देश के करोड़ों लोगों को अब सारा का सारा राशन 2 रुपए किलो सस्ता दे रहे हैं। आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं निकल रहा, 6 महीने रखने पर आपका जो खर्च आता, 2 रुपए 40 पैसे, उसमें से 40 पैसे आप अपने पास रखिए और उपभोक्ता को 2 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो गरीबों को अनाज सस्ता भी मिल जाएगा और 175 लाख टन की भण्डारण क्षमता आपके डिस्पोजल पर हो जाएगी। यह गरीब के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जमाखोरी अपराध है, होर्डिंग बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा होल्डर अगर कोई है, तो वह भारत सरकार है। सरकार ने नॉर्म तय किए हैं कि किस समय कितना अनाज सरकारी गोदामों में चाहिए। उसके मुताबिक जनवरी में 200 लाख टन, अप्रैल में 212 लाख टन, जुलाई में 319 लाख टन, अक्टूबर में 212 लाख टन अनाज सरकारी गोदामों में चाहिए और इसमें 50 लाख टन strategic reserve भी शामिल है। यह बफर स्टॉक हर समय देश में रहना चाहिए, लेकिन फिर आप 700-800 लाख टन क्यों रख रहे हैं? लगभग 400 लाख टन अनाज अधिक हम अपने स्टॉक में रख रहे हैं, यानी होल्डिंग कर रहे हैं और होल्डिंग कर रहे हैं, तो इससे महंगाई बढ़ रही है। देश में महंगाई बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है, तो वह भारत सरकार है। अगर सबसे बड़ा होल्डर कोई है, तो वह भारत सरकार है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी-अभी सब कमेटी, कॉमर्स में चावल के एक्सपोर्ट के सवाल को लिया गया। अधिकारियों से पूछा गया कि जब चावल बहुत अधिक है, तो आप उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? तीनों विभागों के तीनों सचिव आए और बोले कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाए। इस पर कमेटी ने पूछा कि फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो बताया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास मामला है और उस पर फैसला नहीं हुआ है। इसके बाद कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उनसे बात की,

[श्री शान्ता कुमार]

तब एक्सपोर्ट शुरू हुआ और इस समय तक 42 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हो गया। आपने चावल क्यों रोका और समय पर एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया?

महोदय, दुनिया के बाजार में भारत के चावल और भारत के गेहूं का स्थान है और लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप उसको इकट्ठा करके रखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप यह सारा कुछ क्यों कर रहे हैं?

महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, हमारी कमेटी ने इस सुझाव की चंडीगढ़ जाने पर मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल जी से भी चर्चा की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि एक नया काम कीजिए, जब आप procure कर रहे हैं, तब अगर कोई किसान दस टन लेकर आता है, तो उसको कहिए कि तेरा दस टन हमने ले लिया, उसका 50 फीसदी मूल्य तुमको दे दिया, लेकिन अगर तुम चाहो, तो यह अनाज अपने पास रखो, जब हमें जरूरत होगी, तब हम तुम्हारे गोदाम से उठा लेंगे, लेकिन जब हम उठाएंगे, तब हम उसको अतिरिक्त पैसा देंगे। कितना देंगे? एक क्विंटल एक साल गोदाम में रखने का हमारा खर्च 484 रुपए है, अगर इसको हम नहीं रखते हैं और किसान इसको अपने पास रख रहा है, तो आपके 484 रुपए प्रति क्विंटल बच रहे हैं, इसलिए हम किसान से यह कहें कि जब तुम से अनाज उठाएंगे, तब 484 रुपए प्रति क्विंटल तुमको ज्यादा दे देंगे। प्रकाश सिंह बादल कहने लगे कि इससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। गोदाम, भंडारण को विकेन्द्रीकरण हो जाएगा। 60 वर्ष पूरे होने के बाद मैं समझता हूं कि इन बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी है, लेकिन भंडारण न होने के कारण, अनाज सड़ने के कारण एक तरफ भुखमरी से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ 60 हजार करोड़ रुपए का अनाज नष्ट होता है, 50 हजार करोड़ रुपए की सब्जियां और फल नष्ट होते हैं। शर्म आती है, पूरा का पूरा देश उस पर चिंता व्यक्त कर रहा है।

महोदय, मैं बड़ी गंभीरता के साथ सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं। गवर्नेंस की हालत तो यह है कि आज बोरियां नहीं मिल रही हैं, पूरा देश इसके लिए चिल्ला रहा है। देश का किसान खून-पसीना एक करके उत्पादन कर रहा है और उत्पादन नहीं संभाला जा रहा है, इससे बड़ी inefficiency सरकार की क्या हो सकती है? एकदम कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए फौरी तौर ये दो सुझाव मैं देना चाहता हूं और तीसरा सुझाव एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट के बारे में हमारी कमेटी ने कहा और बाद में एक्सपोर्ट हुआ। ये तीन सुझाव मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। 6 महीने का इकट्ठा राशन दीजिए, दो रुपए प्रति किलो सस्ता दीजिए, इससे पूरा राशन उठेगा और 175 लाख टन भंडारण की क्षमता आपके पास और हो जाएगी। एक भी दाना खुले में रखने की जरूरत नहीं होगी। एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए और किसानों को कहिए कि जो किसान अपना अनाज अपने पास कुछ समय रख सकता है, तो वह रखे, उसको 484 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिक मिलेगा। इससे लोग खुश होंगे, उनकी कमाई होगी और हमारा खर्च कम होगा।

अंत में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शर्मनाक स्थिति, यह लज्जाजनक स्थिति, जो बार-बार देखने को मिल रही है, यह समाप्त होनी चाहिए। इस सुझाव पर सरकार विचार करे और इसे तुरंत लागू करे। अगर यह ऐलान कल कर दिया जाए कि 60 साल पूरे होने की खुशी में हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों को अब अनाज दो रुपए प्रति किलो सस्ता मिलेगा, तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): धन्यवाद सर। इस सदन में माननीय सदस्य अनाज का भंडारण करने के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका बहुत शीघ्र समाधान किया जाना किसानों और आम जनता के हित में बहुत आवश्यक है।

सर, इस यूपीए सरकार ने, जिसका लक्ष्य ग्रामीण विकास, यानी गांवों का विकास और किसानों की तरक्की है, उसने इस एजेंडा को लेकर, इन प्राथमिकताओं को लेकर कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं। किसानों को किस तरह से लाभ मिले, इसके लिए यूपीए सरकार कई विधेयक लायी है, जैसे, अभी भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक भी आने वाला है ताकि किसानों से उनकी जमीन जबरन न ली जा सके और किसानों को उनकी फसल की मिनिमम उचित कीमत मिल सके। इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान है। किसानों को कई मौकों पर कर्जा माफी भी दी गयी है और उनके लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की सुविधा भी है।

सर, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और जहां ज्यादातर लोगों की आजीविका, उसके पूरे परिवार की आजीविका, शादी-ब्याह आदि सब कुछ अनाज पर ही निर्भर करता है, फसल पर ही निर्भर करता है और कृषि पर ही निर्भर करता है, वहां आज किसान के सामने बड़ी विषम स्थितियां हैं। जिसे हम इस देश का अन्नदाता कह सकते हैं, उसके सामने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतनी चुनौतियां हैं कि कभी अगर बरसात पूरी न हो तब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, अगर बरसात ज्यादा हो जाए तब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, यदि कीड़े लग जाएं तब उसकी फसल नष्ट हो जाती है और कभी सर्दी में जब ज्यादा पाला पड़ जाए तब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इन कठिनाइयों और चुनौतियों में भी किसान और उसका पूरा परिवार रात-दिन जाग कर फसल की रखवाली करता है और खेतों में रात-रात जाग कर कभी चिड़ियां उड़ाता है और कभी जानवर भगाता है। इतनी मेहनत के बाद अनाज उत्पन्न हो पाता है, लेकिन फिर वह बारिश के कारण सड़ जाता है या खराब हो जाता है, क्योंकि किसान के पास उसके भण्डारण की कोई जगह नहीं है और वह अनाज खुले में रखा हुआ है, तो यह किसान के सपनों पर, उसके अरमानों पर, उसकी मेहनत पर पाला पड़ने वाली बात हो जाती है। इस तरह से उसकी मेहनत पर बिजली गिर जाती है और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है।

किसानों के हजारों-हजार टन अनाज के इस तरह बर्बाद होने की, सड़ने की और उसके भण्डारण की समस्या काफी वर्षों से बड़े प्रखर रूप में सामने आ रही है। एक तरफ जहां लोगों को खाने की परेशानी है, भोजन की परेशानी है और उनके सामने अन्न को खरीदने की

[डा. प्रभा ठाकुर]

परेशानी है कि इतनी कीमत में वे अनाज कैसे खरीदें, वहीं दूसरी तरफ अगर करोड़ों रुपये का अनाज इस तरह से बर्बाद हो जाए, तो इसका कोई न कोई ठोस उपाय होना चाहिए और इसके लिए सरकार उपाय कर भी रही है। उसके लिए सरकार ने कई जगह अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने की शुरूआत की है। कई, अनेक राज्यों में गोदाम बनाने के लिए कुछ प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया है तथा खुद केन्द्र सरकार भी बना रही है। महोदय, जो मुझे जानकारी हुई है उसके अनुसार अनाज के भण्डारण के लिए जो ये गोदाम बनाए जाएंगे, उनका किराया कुछ इस तरह से तय किया है कि गोदाम में कितने टन अनाज आएगा। यहां मैं एक सुझाव यह देना चाहती हूं कि गोदाम की कितनी लम्बाई, ऊंचाई और चौड़ाई है, उसी आधार पर किराया निश्चित होना चाहिए। किराए में टन वाले हिसाब से इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। गोदाम की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से भी उसका किराया निश्चित होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता रहे। मेरी यह एक बात है।

दूसरी बात है, कई जिलों में अभी भी यह आवश्यक नहीं समझा गया है, जैसे मैंने राजस्थान की सूची दी है, अजमेर जिले में अनाज के भण्डारण के लिए एक भी भंडार गृह नहीं खोला जा रहा है, जबकि अजमेर जिले में बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। जयपुर जिले में भी काफी ग्रामीण क्षेत्र है। वहां भी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। इसका मैंने कारण जानना चाहा तो पता चला कि वहां इतनी केपेसिटी है अनाज के भण्डारण के लिए, जिसके कारण अतिरिक्त भण्डार गृह बनाने की जरूरत नहीं है। सर, मेरे तो यह बात गले नहीं उतरी। इन जिलों में जहां यह जरूरी नहीं समझा गया, तो अगर बारिश में वहां अनाज खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार के ही इसी रिसर्च और निर्णय पर आएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे इसको अच्छी तरह से देखें। यह भी सही नहीं है कि कोई बड़ी कम्पनी ने टेंडर दे दिए और उस आधार पर वे भण्डार गृह बनवा रहे हैं। इसके बजाय, अगर जिस प्रदेश के जो लोग हैं, जिस जिले में जो लोग हैं, अगर वे खेती वगैरह से संबंधित हैं, पहले प्राथमिकता उन्हें ही क्यों न दी जाए कि वे ऐसे भण्डार गृह बनाएं, जिससे उनको उसका किराया भी मिलेगा तथा उससे उनकी आजीविका भी चलेगी। इस तरह भण्डार गृह बनाने की सुविधा उस गांव के लोगों को, उस जिले के लोगों को ही मिलनी चाहिए, बजाय किसी बड़ी-बड़ी प्राइवेट कम्पनियों को ठेका दिया जाए। जहां तक गुणवत्ता की बात है, सरकार यह कह सकती है कि निश्चित गाइड-लाइंस के अनुसार अमुक-अमुक एजेंसी के माध्यम से बनना चाहिए। इस तरह से निश्चित किया जाएगा तो उसी जिले के लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी रहेगी और इससे उनको लाभ भी होगा। इसके अलावा अगर कभी अनाज की कमी है या उनकी फसल बर्बाद हो भी गई, तो उनको इस प्रकार से एक लाभ मिल सकेगा।

सर, किसान को इससे एक लाभ यह भी होगा कि भण्डार गृह में उसे औने-पौने दाम में अपनी फसल बिचौलियों को नहीं बेचनी पड़ेगी। मार्केट में जो बिचौलिए हैं, उन्हें लगता है कि किसान कहां जाएगा, क्योंकि इस बार भी अनाज की बम्पर फसल हुई है पूरे देश में। हर जगह बिचौलिए, दलाल हैं, जिनका जमाखोरों से और किसानों से सम्पर्क रहता है। अब उन किसानों

को अपना अनाज मजबूरी में सस्ते दामों में बिचौलियों को इस कारण देना पड़ता है कि कल को बारिश होने की वजह से उनका अनाज खराब न हो जाए। अगर उसको भण्डारण की सुविधा मिलती है तो वह अपनी फसल को चार-छ: महीने रोकने के बाद बेचेगा तो उसको पूरा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इस तरह से भण्डारण की सुविधा होने से किसानों को फायदा मिलेगा। महोदय, बोरियों की कमी होना बड़े आश्चर्य की बात है। अभी भंडारण की बात हुई और अब बोरियों की कमी हो गयी। अगर किसान के पास बोरियां नहीं होंगी तो वह अपना अनाज किस में भरेंगे? महोदय, कई गांवों में यह एक पुरानी परम्परा रही है कि किसान जब अपने घरों में अनाज का भंडारण करता है, तो अनाज खराब न हो और उसमें कीड़े न लग जाएं, इस के लिए वह उसमें पारे की गोलियां डाल देता है। यह इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है। किसान पारे की गोलियों को छोटी-छोटी पोटलियों में बांधकर अनाज में डाल देता है ताकि अनाज सुरक्षित रहे, लेकिन अगर पारे की एक भी गोली अनाज के साथ चली गयी और पिस गयी तो वह इंसान के जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसके लिए भी गांवों के किसानों में जागृति लायी जानी चाहिए कि वे इसका प्रयोग न करें। महोदय, किसानों के लिए भंडारण की अच्छी व्यवस्था होने के बाद किसान पारे की गोलियों की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे।

महोदय, आखिर बोरियों की एकदम shortage कैसे आ गयी? हमने अनाज की shortage के बारे में तो सुना है, लेकिन अब बोरियों की shortage भी होने लगी। यह बड़े आश्चर्य की बात है और इसमें देखना यह भी होगा कि shortage वाकई हुई है या की गयी है? यह एक अचरज की बात है। इस पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे क्योंकि अनाज के व्यवसाय से जुड़े सटोरिए और बिचौलिए भी मिलकर किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने हित में इस तरह के करतब करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए न केवल केन्द्र सरकार बल्कि सभी राज्य सरकारों को भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। महोदय, यह केवल केन्द्र सरकार का ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि वे किसान को उसके अनाज के भंडारण की पूरी सुविधा प्रदान करें ताकि हमारा किसान जो अनाज पैदा करे, वह बर्बाद न हो, वह उसे समय पर बेच सके और उसे फसल के पूरे पैसे मिलें। अभी शान्ता कुमार जी ने अनाज के एक्सपोर्ट की बात कही। महोदय, हमारी यू.पी.ए. सरकार जल्द ही फूड सिक्युरिटी बिल संसद में पेश करने जा रही है। यह हमारी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें यू.पी.ए. अध्यक्षा सोनिया जी की बड़ी रुचि है ताकि आम आदमी को दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल उपलब्ध हो सके। महोदय, जब सरकार के पास इतना अनाज है तो लोगों को सड़ा अनाज देने की क्या आवश्यकता है? लोगों को राशन मिले क्योंकि सड़े हुए अनाज को फेंकने से अच्छा है कि लोगों को अच्छा अनाज मिले क्योंकि उसके सड़ जाने पर तो उसे जानवर भी नहीं खा सकेगा।

महोदय, इन सब बातों को सरकार के ध्यान में लाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भंडारण की अच्छी सुविधा किसानों को दें। साथ ही सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि उसी स्टेट

[डा. प्रभा ठाकुर]

व जिले के लोगों को भंडार गृह बनाने की सुविधा प्रदान करें। आप खाली एक ही एजेंसी को भंडार गृह बनाने का काम न दें ताकि स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके क्योंकि बारिश व ओले गिरने के बाद यदि फसल की सुरक्षा भी की जाती है तो उसमें किसान का नुकसान ही होगा। हमारे यहां कहावत भी है कि जानवरों के फसल चरने के बाद यदि बाड़ लगायी भी गयी तो उसका क्या फायदा है? इसलिए समय रहते सरकार, जिसकी नीति किसानों के हित की रही है, गरीबों के हितों को प्राथमिकता देने की रही है, इस बारे में त्वरित कार्यवाही करे कि वर्षा से पहले भंडारण की ऐसी स्थिति बन जाए कि कहीं भी गोदामों में अनाज न सड़े। चाहे आप अनाज एक्सपोर्ट करें या सस्ते दामों पर आम लोगों को मुहैया कराएं, इसके लिए जो भी व्यवस्था में कमी है, उसे दूर किया जाए ताकि किसान और आम जनता को अनाज के मामले में पूरी सुविधा मिले।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में खाद्यान्न भंडारण की समस्या के संबंध में हो रही चर्चा में शामिल होने का आपने जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर से खाद्यान्न भंडारण की समस्या देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह इसलिए बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुतायत संख्या में किसान गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की खेती करते हैं, लेकिन किसानों की उपज का भंडारण सही न होने की वजह से सरकारों के नियंत्रण में गेहूं और दूसरी उपज का रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है।

महोदय, हमारे देश में जो उत्पादन की क्षमता है, उसे किसानों ने अपनी कर्मठता और मेहनत से लगातार बढ़ाने की कोशिश की है। वर्ष 2011-12 में किसानों ने अपनी क्षमता से धान के उत्पादन में वृद्धि की है और इस तरह धान का उत्पादन करीब दस करोड़ टन हुआ है। गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा है, करीब नौ करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा मोटे अनाजों और दालों का उत्पादन भी बढ़ा है। हमारे देश के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन केन्द्र की सरकार देश की जरूरत के हिसाब से अनाजों के भंडारण की व्यवस्था करने में कहीं न कहीं अभी तक नाकाफी नजर आई है।

[(उपसभाध्यक्ष (श्री शान्ता कुमार) पीठासीन हुए)]

महोदय, जब भी बरसात का मौसम होता है, तो बहुत से भंडारण में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि गेहूं के भंडारण में बरसात का पानी आ जाता है और गेहूं खराब हो जाता है और बहुत से भंडारण में चूहे घुस कर गेहूं को कुतर कर बर्बाद कर देते हैं। इस तरह कई तरीके से हमारे देश के किसानों द्वारा उपजाया हुआ गेहूं, अनाज और दूसरी फसलों का नाश भंडारण की कमी की वजह से होता रहता है और जो सही आदमी, गरीब आदमी है, जो रोजी-रोटी के लिए मोहताज है, उसको हम खाना भी नहीं दे पाते। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें साल 2011 में देखी है, जैसे हमारे जनपद गाजियाबाद के हापुड़ शहर में बड़े पैमाने पर हजारों टन गेहूं बरसात की अधिकता और भंडारण की व्यवस्था बेहतर

न होने की वजह से सड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर सरकार के पास गेहूं के भंडारण की व्यवस्था बेहतर नहीं है, किसान की उपज को सही से रखने की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम उस अनाज को गरीबों में मुफ्त में बांट दिया जाए। इस तरह देश की सर्वोच्च न्यायालय सरकार के इस खाद्यान्न प्रबंधन पर शायद प्रश्न-चिह्न लगा रही है। हमें चेतना होगा, सरकार को चेतना होगा।

इसलिए मैंने इस मुद्दे पर पहले भी कई बार अपनी पार्टी की ओर से विचार रखा है कि जिस प्रकार से सरकार ने अलग से रेल बजट बनाकर रेल विभाग को बेहतर करने की दिशा में प्रयास किया, उसी प्रकार की व्यवस्था कृषि के लिए भी होनी चाहिए। मैंने अनेक बार सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने की कोशिश की कि चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, अत: कृषि विभाग को भी अलग से बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत रख लिया जाए, खाद्यान्न व्यवस्था के लिए समुचित धन की व्यवस्था कर ली जाए और खाद्यान्न के रख-रखाव के लिए वेयरहाउसेज़ की स्थापना कर दी जाए। यदि ऐसा हो जाए, तो हमारे देश में जो खाद्यान्न के सड़ने और खराब होने की शिकायतें आती हैं, सरकार इनसे निजात पा सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने बहुत बेहतरीन और उपयोगी विचार सदन के सामने रखकर गेहूं और दूसरी उपजों के रख-रखाव के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। चूंकि हम लोग खेत-खलिहानों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं सरकार की अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह बात सही है को वेयरहाउसेज़ की कमी है, अब वह बजट की कमी की वजह से है या इच्छाशक्ति की कमी की वजह से है, यह हम नहीं जानते, लेकिन यह बात सत्य है कि गेहूं और दूसरे अनाज कहीं न कहीं व्यर्थ हो रहे हैं, चाहे बरसात के पानी के कारण, चाहे चूहों के कारण या अन्य कारणों की वजह से। हम लोगों ने गांवों में भी यह सब देखा है। गांवों में पंचायत लेवल पर भी पंचायत वेयरहाउसेज़ बने होते हैं। चार-चार या पांच-पांच गांवों की एक पंचायत होती है, जिसे न्याय पंचायत कहा जाता है और पांच-पांच या छह-छह न्याय पंचायतों का एक ब्लॉक होता है और कई-कई ब्लॉकों की एक तहसील होती है। यदि माननीय मंत्री जी और सरकार के नुमाइंदे मेरी बात पर ध्यान देंगे, तो मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि सरकार न्याय पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों के समूह को संगठित करके, उनकी कमेटी या समिति बनाकर, सरकार की ओर से सब्सिडी देकर, उनको इस बात का अधिकार दे दे कि वे अपने गेहूं के भंडारण के लिए आपस में coordination करके, सरकार की सब्सिडी और अपने प्रबंध से न्याय पंचायत स्तर पर गेहूं और फसलों के भंडारण की व्यवस्था के लिए कुछ वेयरहाउसेज़ का निर्माण करें। यदि यह पहल सरकार करती है, तो निस्संदेह गेहूं के भंडारण की समस्या में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी।

मैं समझ सकता हूं कि देश बड़ा है और सरकार के सामने बहुत सी मुश्किलें, जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष और तमाम दलों के लोग हमेशा इस बात की चिंता

[श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप]

करते हैं कि देश का जो भी उत्पादन है, किसानों को उस उत्पादन का सही दाम मिले और जो उत्पाद हमारे देश में पैदा हुआ, वह सही रूप से लोगों के घरों तक पहुंचे। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि इसके लिए थोड़े निचले स्तर पर जाकर आप सोचें, स्टेट गवर्नमेंट के अफसरों की मदद लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों की मदद लें, पंचायत लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर आप कोई कमेटी बनाकर या किसानों के समूह को संगठित करके, आप उन्हें इसके लिए authorize करें कि वे कुछ फंड सब्सिडी के जरिए और अपने पास से कुछ फंड लगाकर पंचायत लेवल पर स्वयं ही ऐसे भंडारणगृहों का निर्माण करें, जिनके जरिए उनकी उपज को सही तरीके से रखने की व्यवस्था हो सके।

उपसभाध्यक्ष जी, खाद्यान्नों के भंडारण के साथ-साथ हमारे देश में एक मुश्किल और आती है कि हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हालांकि यह बात विषय से हटकर है, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में इसलिए कहूंगा, क्योंकि यह खाद्यान्न से जुड़ा हुआ मामला है। आज देश के बहुत सारे प्रदेशों में जो सस्ते राशन की दुकानें हैं, उन पर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो गेहूं और चावल गरीब लोगों में, BPL श्रेणी के लोगों में बंटना चाहिए, वह नहीं बंट पाता है। एक तरफ हमारा अनाज भंडारणगृहों में सड़ रहा है, बरसात की वजह से खराब हो रहा है, उसे चूहे खा रहे हैं और दूसरी ओर हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। सरकार को इस समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने उस अनाज को बरसात से खराब कराने के बजाय, उस अनाज को चूहे और दूसरे पक्षियों को खिलाने के बजाय अगर सरकार distribution व्यवस्था को बेहतर करके देश के गरीब लोगों में बांटने की व्यवस्था करती है, तो शायद देश के गरीब लोगों को भुखमरी से निकलने का मौका मिल सकता है।

महोदय, लम्बा ज़माना हो गया, हमारे देश में बी.पी.एल. सूची का रिव्यू नहीं हुआ है। आज मैं यक़ीन के साथ और सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें करोड़ों लोग बी.पी.एल. श्रेणी की सूची में आते हैं, लेकिन सरकार उस सूची का रिव्यू नहीं कराती है। जो बहुत से गरीब लोग हैं, उनको बी.पी.एल. श्रेणी का लाभ नहीं मिलता और जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, वे उसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को दूसरा सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि जहां हमें खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, वहीं यह खाद्यान्न गरीबों के घरों में जा सके, इसके लिए distribution व्यवस्था पर भी हमें कोई न कोई कारगर नीति बनाकर गरीबों तक उस अनाज को पहुंचाना होगा।

महोदय, हमारे सदन में बोरियां कम होने का मामला कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। सत्ताधारी पार्टी की माननीय सांसद महोदया ने भी उस पर चिन्ता व्यक्त की है। अब चिन्ता व्यक्त करना तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार के हाथ कहां बंधे हैं? बोरियों के उत्पादन को बढ़ाने से सरकार को किसने रोका है? भंडारण बनाने की व्यवस्था करने से सरकार को किसने रोका है? गेहूं की उपज को बचाने में सरकार के सामने मुश्किल कहां है? इसलिए मैं

कहूंगा कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश और समाज के लोग भरोसा नहीं करेंगे। जब हम बोरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो warehousing कैसे देंगे? लोग हम पर कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए इस पर भी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और देश के किसान, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों से जुड़ा है। मैं सरकार के लोगों से अपील करूंगा कि वे भी इसको गंभीरता से लें। बहुत लम्बा समय गुज़र गया यह कहते-कहते कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, लेकिन हर साल बरसात होती है, फिर अनाज खराब होता है और गरीब लोग भूख से तड़पते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करें, ताकि गेहूं का भंडारण भी बेहतर हो सके और जो अनाज हमारे देश में पैदा हो रहा है, वह सही घर और सही मुंह तक पहुंच सके। ...(**समय की घंटी**)... देश के लोग, जो जीने का अधिकार हमारे बाबा साहेब डा. अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के ज़रिए मांगते हैं, उनके जीने के अधिकार को हासिल करने के लिए कम से कम दो वक्त की रोटी उनको मयस्सर हो सके, इसका तो कम से कम आप प्रबन्ध कीजिए। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, actually, the main issue is why the people, at large, in our country are not getting foodgrains at an affordable price. Why has the country been witnessing deaths due to hunger? Why have there been deaths due to heavy quantum of debt on their heads? Sir, when I was a school student—I still remember that—Jawahar Lal Nehru once said, ".......blackmarketeers will find themselves hanging from the lamp post." I was very much inspired. But, now, after 60 years, we are witnessing in States the poor farmers hanging themselves in their homes. Sir, many say, this situation has arisen because agriculture depends on weather conditions. Then, another argument was placed. However, now it is not there in that voice that everywhere the prices are rising—it is a world phenomenon; every country is facing this problem.

Sir, I remember, in this particular House, a data—published by an 'The Economist' (Magazine) was quoted giving information as to how many important countries, particularly, the neighbouring countries, are dealing with this problem of price rise, including the rise in diesel and petrol prices. Looking at those pictures, we have found that our country is in a very bad situation. Now, Sir, during the last five years, a huge quantity of foodgrain has been damaged. This situation has been there for the last few years. Previously, we did not have this situation. At least, it was not there so much, previously, in the agenda of the Government, and, therefore, the Supreme Court had to intervene. During the above period, we have experienced a steep rise in the prices of essential commodities. Sir, how

[SHRI PRASANTA CHATTERJEE]

many times have we discussed this issue here in one form or the other? We have discussed here Arjun Sengupta's report—'Rupees 20 per head per day.' If you recall, Sir, even today, the Minister placed some figures here as to what is the picture regarding the essential food commodities. I also have some information which I got from the Monthly Average Retail Price of about 42 food articles. The Mustard Oil price which was Rs. 76.56 last year has now gone up Rs. 100. This figure has been quoted by the Government. Same is the case regarding many other food items. They are listed here. Potato is there; tomato is there; onion is there. So, this is the picture. Sir, how will the people survive in just twenty rupees? It is amazing. In Delhi, how will the people afford monthly rent? Transport expenses are there; education, medical, and clothing expenses are there. Anyone of us can experience it. Sir, can one survive in just twenty rupees? It has been published that 60 per cent of our population have no water connection, have no access to sanitation facility. If somebody goes to 'Pay and Use Toilet', how much one has to pay for its usage, for taking bath? So, how will the people survive? If, roughly, Rs. 2 per head is charged with a family of 5 heads Rs. 10 (Rs. 5×2) is spent there. This is the actual situation there in the whole country.

Sir, we have a good monsoon. The country experienced a very good monsoon. But the prices have not been reduced. So, all these theories are bogus theories, that this phenomenon is there in the entire world, that it depends on the weather conditions, etc. Even today, in reply to an Unstarred Question, it is said that 'We have a plenty of stock—Rs. 750 lakh tonnes as on 1st June, 2012 against the last year's stock of Rs. 654.73 lakh tonnes.' But still we are experiencing steep rise in the prices of essential commodities. Why is it there, Sir? A huge stock is there, but still the people are suffering; the poor people are suffering. Sir, we had demanded a ban on forward trade on Essential Commodities. I remember, once the Finance Minister had said here that they would try to do that for one or two items. But nothing has happened. The other side has rejected our demand for having a universal PDS at an affordable price. They have rejected the demand. They were to tell us about how to tackle this problem. Now, today, in the reply given to an unstarred question, it was said that 'foodgrain godowns in the country are not in a poor condition. However in a portion it has been said some quantity of foodgrains get damaged due to rains, floods and other natural calamities.' This was the reply given!

Now, what about the irrigation system in our country? How much money has been spent in the Budget. What is the quantum of coverage there? Even after 60 years of Independence, people depend on *Allah!*

Sir, unless the Government changes its mind, unless there is a shift in policy towards the people, especially the poor people, things will not change. I would like the present-day Government to ponder over these issues and consider the demands raised by us.

Thank you, Sir.

SHRI N. K. SINGH (Bihar): Mr. Vice-Chairman, as we look at the analysis and statistics in relation to the Public Distribution System, we are really reminded of what the Bourbons had once said—'learning nothing and forgetting nothing'. If you look at the history of famines in India, it is evident that the major famines in India have not been caused by shortage of foodgrains, but they have been caused by the distortions in the Public Distribution System. In 1943, writing about the famous famine of Bengal, Prof. Amartya Sen said that three million people died in that famine, not because foodgrains were in awesome short supply, but because of the artificial distortion with which the entire Public Distribution System was confronted. Many years down history, Government does not seem to have learnt any lesson, and that is why I said, almost like the Bourbons—'forgetting nothing and learning nothing'.

Now, what are the facts, Sir? Broad facts remain that the total storage capacity in the FCI godowns is 300 lakh tonnes. If you add a 154 lakh tonnes, as far as the States are concerned, the total storage capacity is 454 lakh tonnes, against a figure of 654 lakh tonnes, as was the entire stock available on the 6th of June, 2011, a shortage, clearly, of 200 lakh tonnes, accepted by the Government itself. For instance, look at the implications of this. The Nandi Survey conducted in only 112 districts in India suggests that 42 per cent children under the age of five are underweight, and 59 per cent of the children are stunted; half of them are below the age of two years. The Supreme Court was, naturally, therefore, prompted in 2010. And, what did they say? What they said is rather pathetic and telling, and I quote from the judgment of the Supreme Court. They said, "Give it to the hungry poor instead of the grains going down the drain." That is what Justice Bhandari and Justice Verma had said. And the Court directed the Government to establish adequate godowns so that the foodgrains which were rotting could be given easily to the poor.

[SHRI N.K. SINGH]

4.00 P.M.

Very little action has taken place after the Court judgment. In fact, 26 million tonnes are required to maintain a buffer stock. What we have stocked is more than what is required. According to the Agriculture Minister, the FCI is losing almost Rs. 27 crore a day. According to the admission made by the Minister himself, Rs. 28,000 crore has been lost to Government, which is adequate to feed two crore people in one year in the last decade on account of the distortion in the foodgrains. The distribution loss, which is 30 per cent of the grain supplied, plagues the entire distribution system. It doesn't reach the Government. Government has acknowledged that Rs. 58,000 crore worth of foodgrains every year is really destroyed due to the storage shortage. In fact, Mr. Thomas, you yourself had admitted it in the recent statement, and also in the written reply. I quote from your speech in which you say, "There is a wastage of food, starting from the point of harvest, procurement, storage, distribution, transportation and even at social functions like marriages." I think, you are very correct. But it is for you to come up with a game-plan. Look at the astonishing figures. Only two per cent of the fruits and vegetables in this country, Sir, is processed. This is in contrast to 30 per cent in Thailand, 70 per cent in Brazil, 78 per cent in Philippines, and 80 per cent in Malaysia. Between 15 and 20 per cent of the cooked food on special occasions is really wasted. And 30 per cent of the country's fruits and vegetables are perished due to absence of adequate cold-storages. In the light of all these very grim but very telling statistics, Mr. Minister, you must look for out-of-the-box solution. You must look for some innovative answers. I have for your consideration seven suggestions today. My first suggestion is, abolish the inter-State food sales which takes away the distortions of India as a free market. We have one large common market. But your restrictions on movement of foodgrains from one zone to another, or, from one State to another is something quite mind-boggling. When will India have one free common agriculture market to really prevent these kinds of distortions? Think about it. It is time we should do so. Second, do not force the FCI to buy the entire amount that the farmers sell. This is the policy which is fraught with danger. You have shortage of 200 lakh tonnes of storage capacity. You cannot have a magic wand forcing the FCI into courses of action, which are non-commercial and non-remunerative. It is something which we should think of. Third, technology permits you to be able to track down the country's gross consumption figures and for storage what you require in that

particular zone. Fourth, have an on-line tracking system in which you are able to track down the rotting foodgrains and improper storage and to also know where these areas of shortage and deficiency lie. Have a system where technology can enable you more expeditious and more efficacious use of the food material you have. Fifth, Sir, right back in 1979, you had agreed as part of the 'Save Grain Campaign' to have one good storage capacity in every sub-division and even in large panchayats, certainly in districts. Have modern silos; have Public-Private Partnership; and incentivize it in a manner far more than you have been able to succeed. What you have done so far has been inadequate to get Public-Private Partnership going, particularly at the local levels of administration. Sixth, get rid of this peculiar distortion. Bihar, for instance, has little or no procurement of foodgrains. Almost every district in Bihar does not have the capacity to be able to store foodgrains. Get rid of this obvious large distortion between areas which are endemically consumption, production and storage deficits. Finally, Sir, you are going to have the Food Security Bill and the Food Security Act, which is on the anvil. That will, Mr. Minister, compound your problems. Sir, the Finance Minister in his Budget speech was audacious enough to suggest that we should look to new experiments. Look at the ability in which you can give perhaps food coupons or make direct cash transfers, make use of the kind of Unique Identification Number, which the Nilekani Committee has given you. Look to solutions, which do not cast a disproportionate burden on your over-frayed and over-exerted bureaucracy. Look to solutions which are innovative. Let not India have the disrepute of being seventh in the global index of hunger and also a country vulnerable to famine and endemic food shortages. Wake up, think afresh. Thank you very much, Sir.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, today, we are discussing the great Indian paradox—'shortage in the midst of plenty'. We have plenty of foodgrains. From 1950, we have quadrupled our food production. We have increased it from 50 million tonnes to 100 million tonnes; from 100 million tonnes to 150 million tonnes, and, from 150 million tonnes to 200 million tonnes, and, now we are crossing 250 million tonnes. This is how we are progressing. It is true but, as also said by hon. N. K. Singh ji, we are 7th or 8th in the hunger index in the world. Why is it so? This is the paradox we must understand, and, we must try to solve, and, through you, Sir, I would like to request the Minister to understand it and do something.

[SHRI D. BANDYOPADHYAY]

Sir, the point is that we have reached, I won't say, the Chinese level of 500 million tonnes, but our production is sufficient at our own level to feed our own people, yet we are unable to do so. The causes are very well known. It is not shortage of food. It is the inability to access the food. We do not have the ability to access the food because we do not have the purchasing power, because we are poor, and, therefore many of us cannot eat that. I would not like to go very deep into this dissertation, but I would like to make two, three short and practical points for the consideration of the hon. Minister.

First of all, we succeeded fairly well in the late seventies with the Food-for-Work Programme. It was a very good success. It did two things. The hungry people got food directly and the supply of food into the market was directly through the workers, resulting in stability in prices in the food market, in the grain market, deep in the rural areas. I would humbly suggest to the Government to consider paying wages in half cash and half food in the MGNREGA scheme where you pay wages in cash. In this way, you can push foodgrains directly into the deep interiors of the country, and, thereby, stabilize the food prices which go up and up all the time. This is my first suggestion, which I would like to make for consideration by the hon. Minister.

Secondly, it is true that we cannot give doles directly in the way we should do it but the point is that since the Famine Code of late nineteenth century, which followed the Deccan riots, frequent riots caused by dreaded famine, we have a system of free distribution of foodgrains to the utterly poor people. We have now the BPL list, and, we also have stratified list of people who are at the lowest rung of the BPL. Why should we not give food directly to such targeted families instead of paying them cash? It is a limited amount, but it goes. Two things happen. Food goes in; where there is demand and the wealth of the nation goes up.

Then, Sir, we have already heard that 55 per cent of our children are malnourished or underweight. Why? Because they don't get food; their parents don't get food. So, it is time that we pack our Mid Day Meal programme in such a way that it becomes slightly more nutritious and a little more in quantity. Sir, in many places, Mid Day Meal is really the only meal that is given to the children. After that, many children don't get any other meal. So, Mid Day Meal should be much more in quantity and much more nutritious.

Then, Sir, we are really talking about two things. In the morning, we had a discussion on FCI. In fact, the question on FCI was the leading question. The answer was almost inherent in the question that it is a white elephant. FCI is one major institution that was created by the then Government to protect India's food sovereignty, and to protect India's food sovereignty, Sir, is to protect Indian political sovereignty. Therefore, under no circumstances, we should do anything which dismantles the FCI or reduces its efficiency. Yes, there is scope for development; there is scope for improvement; there is scope to increase the efficiency many times over. I have nothing to question about that. But, never question the need of FCI which protects the food sovereignty and, therefore, the political sovereignty of our country.

Lastly, Sir, make sure that all the foodgrains that are there are kept in a way that they don't rot. I understand the problem. You have a capacity of forty-four-and-a-half million tons. You have to keep a buffer of 6.5 million tons. Your procurement is going up by another 7/8 million tons; and you don't have the place to store. It is true. But, give it back to the farmer. In fact, it is your own suggestion that give it back to the farmer. Let him keep it for the time being and withdraw it from him when you require. Therefore, the movement of foodgrains would be lesser. With these few suggestions, Sir, I thank you.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश में कानपुर में एक दुकान है, वहां एक बोर्ड लगा है – "ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको मैंने ठगा नहीं।" नीचे लिखा है – "ठग्गू के लड्डू"। यह बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूं कि ऐसी एक दुकान है और उसकी सबसे ज्यादा बिक्री भी होती है। मेरे ख्याल से वह बोर्ड आपकी सरकार ने अपने आप लगा लिया है कि "कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको हम ठगेंगे नहीं"। सरकार क्यों सुप्तावस्था में चली गई? आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे करें? मुझे उस दिन हंसी आई, जब माननीय कृषि मंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे। किसानों की समस्या के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसमें माननीय मुकेश अंबानी, माननीय आदि गोदरेज, मैं पूरा नाम नहीं जानता, ये लोग शामिल हैं। अब टाटा, बिरला और इनफोसिस वाले, जो रह गए हैं, उनको भी आप कमेटी में रख दीजिए, तो शायद वे किसानों के लिए बहुत अच्छी राय दे देंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, यह जवाब सदन में दिया गया है। किसानों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, जिसने किसानों की उन्नति के लिए राय दी, माननीय कृषि मंत्री, शरद पवार जी पिछले हफ्ते इस सदन में क्वैश्चन का जवाब दे रहे थे, उन्होंने इसके सदस्य के जो नाम बताए, श्रीमन्, सुन कर शर्म आई कि इस देश के किसानों के साथ मजाक हो रहा है। आप दो मजाक कर रहे हैं। अगर आपने कमेटी में एडवाइज के लिए किसानों को लिया होता, तो शायद

[श्री नरेश अग्रवाल]

वे सही एडवाइज़ करते। दूसरा, किसानों की उपज का दाम तय करने के लिए जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ कमीशन है, उस कमीशन में भी आपने सब आईएएस बिठा दिए हैं। जिन्हें गेहूं, जौ की बाली का पता न हो, वे स्क्वायर फीट में जोड़ देते हैं कि उसमें कितना बीज पड़ा, कितनी खाद पड़ी और आप किसान की उपज का दाम तय कर रहे हैं? जब आप इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, तब यह स्थिति आपके सामने आ रही है।

श्रीमन्, यह वही देश है, हमने भी देखा है कि लाल गेहूं इस देश में अमेरिका से आता था और इस देश के लोग लाइन लगा कर उस लाल गेहूं को, जिसकी बीयर अंग्रेज लोग पी लेते थे और उसके बाद उस गेहूं को हिन्दुस्तान में बेचते थे, लेते थे। हिन्दुस्तान के लोगों ने उसी गेहूं को खा-खा कर, हरित क्रांति लाकर, अपने खेत से उत्पादन बढ़ाया और इस देश को आत्मनिर्भर किया। लेकिन, जिस किसान ने देश को आत्मनिर्भर किया, उस किसान के लिए आपने क्या किया? हम बजट में कहते हैं कि हमारा बजट गांव की ओर का बजट है और 70 प्रतिशत गांव में रहने वाली जनता को हम बजट से लाभ दे रहे हैं, अगर लाभ दे रहे हैं, तो आज किसानों के सामने समस्या क्यों है?

श्रीमन्, आज विश्व के अधिकांश देशों में किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, वह डायरेक्ट दी जाती है, किसान के उत्पादन की मार्केटिंग की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आपने क्या दिया? आप बीज महंगा दे रहे हैं, खाद महंगी दे रहे हैं, पानी महंगा दे रहे हैं और लेबर महंगी दे रहे हैं। आप किसान को सब कुछ महंगा दे रहे हैं, लेकिन किसान का उत्पादन आप सस्ते में ले रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जब तक आप गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं करेंगे, तब तक इस देश का किसान सम्पन्न नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे जवाब दें, तो वे APC के मेम्बर्स के नाम पढ़ें और मैंने एडवाइजरी कमेटी के दो सदस्यों का नाम लिया और तीसरे अपने डॉक्टर साहब, जो यहां मेम्बर हैं, वे उसके मेम्बर थे, बाकी और लोग थे। मैंने जो नाम लिया, तब आप जवाब दीजिएगा, तब आप बता दीजिए कि मैंने गलत तो नहीं कहा। अगर मैं सही कह रहा हूं, तो इसमें सुधार लाने की जरूरत है या नहीं है? आप इस पर विचार कीजिए।

आप पंजाब में सौ प्रतिशत गेहूं खरीदेंगे, हरियाणा में सौ प्रतिशत गेहूं FCI खरीदेगी, आन्ध्र प्रदेश में सौ प्रतिशत गेहूं FCI खरीदेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत ही FCI खरीदती है। हमारे प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो वह भी आप जवाब में कह दीजिएगा। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में इतना गेहूं उत्पादित कर सकते हैं, जिससे हम पूरे देश को खिला सकते हैं, बाकी तो सरप्लस गेहूं जाएगा।

श्रीमन्, यही चावल का हाल है। उत्तर प्रदेश में FCI ने लेवी चावल लेना बंद कर दिया, जिसके कारण चावल गोदामों में पड़ा हुआ है, लेकिन उत्तरप्रदेश में चावल खरीदने वाला कोई नहीं है। आप कौन-सी पॉलिसी बना रहे हैं? इस कंट्री को हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहें, इस कंट्री की economy, इस कंट्री का बजट हम एग्रीकल्चर बेस्ड बनाएं, हम कहें कि हम गांव में

रहने वालों के हित का बजट बनाएंगे और हमारी जो आर्थिक उन्नति है, वह गांव से होगी, एक तरफ तो हम यह नारा दें, दूसरी तरफ अगर उनके उत्पादन को हम ठीक से नहीं रखेंगे, तो क्या स्थिति होगी? आज भी, माननीय मंत्री जी, कितने परसेंट लोग भूख से मर रहे हैं, जबकि अपना कितना अनाज सड़ रहा है?

श्रीमन्, जब आप अपनी सीट पर बैठे थे, तब आपने खुद quote किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपसे क्या कहा? मैं न्यायालय के कहे पर नहीं जाता हूं। मैं तो practical आदमी हूं और practical बात करता हूं, लेकिन जब तक आप सत्यता को नहीं देखेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आज भी "दैनिक जागरण" ने निकाला है कि अगर Food for All देश में लागू कर दिया गया, तो हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं होगी, तब हम अनाज कहां पर रखेंगे? आज भी आप जितना खरीद करते हैं, उनमें से करीब 12 लाख मीट्रिक टन अनाज बाहर पड़ा हुआ है।

हमने सवेरे आपसे प्रश्न किया था, तो आपने कहा था कि हमने PPP मॉडल पर स्टोरेज capacity बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। श्रीमन्, आप जरा उसकी कंडीशन्स पढ़ लीजिए। मैंने बहुत लोगों से बात की, हमने अपने यहां भी लोगों से बात की कि मंत्री जी ने कहा कि आप गोदाम बना लीजिए, हम उस पर आपको किराया देंगे। लोगों ने जवाब दिया कि जमीन की कीमत और उसके निर्माण की कीमत जितनी है, वह economically viable नहीं है, इसलिए FCI का यह proposal हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो आप हमारी बात का जवाब दे दीजिएगा। मैंने इसी लिए सवेरे आपसे पूछा था कि आपने जो प्रस्ताव भेजे, आपको प्रस्ताव दिए हुए दो साल हो गए, दो साल में कितने लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कितने लाख मीट्रिक टन अनाज के स्टोरेज के लिए आपकी PPP मॉडल पर गोदाम की व्यवस्था हो गई? यदि नहीं स्वीकार किया, तो आप उस पॉलिसी में बदलाव क्यों नहीं लाते हैं? ...(**समय की घंटी**)... जब तक प्रस्ताव economically viable नहीं होगा, तब तक निजी क्षेत्र का आदमी उस पर धन खर्च नहीं करेगा, जैसा कि हमारे और लोगों ने सजेशन्स दिया।

श्रीमन्, जब आप बोल रहे थे, तब आपने कहा कि आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सजेशन दिया कि 50 परसेंट किसान को एडवांस दे दीजिए और स्टोरेज उसको करने दीजिए। सर, आपने तो 485 रुपए कहा, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप किसान से कह दें कि आप स्टोरेज के लिए ढाई सौ रुपऐ बाद में दे देंगे, तो किसान वही गेहूं और वही अनाज 50 परसेंट कम पर सम्भाल कर रख लेगा। आपने तो 485 रुपये कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप किसान को ढाई सौ रुपये प्रति बोरा एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो वही किसान अपने गांव में उसी अन्न को सम्भाल कर रखेगा और फिर न उसे चूहे खाएंगे, न उसे कीड़े खाएंगे, न वह सड़ेगा और हमारे देश का जो अनाज है, वह सही तरीके से रहेगा। मंत्री जी, हम कह रहे हैं कि आप कम से कम कुछ हिम्मत तो कीजिए। हम उतर भारत वाले चौबीस घंटे राजनीति करते हैं, हम हिम्मत करते हैं, हम निर्णय लेने की हिम्मत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों में क्षमता है, पता नहीं, वह क्षमता आप लोग क्यों नहीं लेते? आप वह क्षमता पैदा कीजिए और निर्णय लीजिए।

[श्री नरेश अग्रवाल]

हमारे पुराने डिप्टी चेयरमैन साहब हंस रहे हैं। मैं बड़ी-बड़ी बातों को कड़वा तो कह रहा हूं, लेकिन सत्य भी कह रहा हूं। मैंने हरदम यह कहा कि लीडरशिप उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। लीडरशिप भारत के किसी और कोने से नहीं निकलती है, बल्कि हमारे यहां से निकलती है। यह निर्णय लेने की क्षमता ही है कि आज सरकार अनिर्णय की स्थिति में खड़ी है, सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जहां दर्द देखो, वहां पर सुन्न कर दो, वहां पर ऑपरेशन न करो, यानी वहां खाली सुई दे दो, जिससे दर्द बन्द हो जाए। इन सब चीजों से कभी समाधान नहीं होता है।

माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और कहूंगा कि आपके एफसीआई के अधिकारियों की यह पॉलिसी है कि अगर उत्तर प्रदेश में जनता को गेहूं की जरूरत पड़ेगी, तो उसे पंजाब से भेजा जाएगा और अगर पंजाब में जरूरत पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश से भेजा जाएगा, जबकि उसी जिले में गेहूं और चावल मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एक जिले से दूसरे जिले को नहीं दिया जाएगा। आप इस पॉलिसी को नोट कर लीजिए कि आपने ऐसी कौन-सी पॉलिसी बनायी है। अगर मेरे हरदोई में चावल और गेहूं पीडीएस को चाहिए, तो उसकी अलॉटमेंट हरियाणा से मिलेगी। वह हरियाणा से हरदोई आएगा, लेकिन हरदोई के गोडाउन में जो रखा है, वह हरदोई को नहीं मिलेगा। आपके एफसीआई के अधिकारियों ने जो यह एक बहुत बड़े गबन और घपले की पॉलिसी कर रखी है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसान के लिए चिन्ता कर लेंगे, तो शायद 2014 में आप उम्मीद कर लेना, लेकिन अगर आप चिन्ता नहीं कर रहे हैं, आप जहाज को डुबोना ही चाहते हैं, यदि आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि जहाज को डुबोना है, तो फिर यह होता है कि डूबते को सहारा नहीं दिया जाता, बल्कि राजनीति में डूबते को और डुबो दिया जाता है। हम उत्तर प्रदेश में आपको डुबोने के लिए तैयार हैं। अगर आप सुधार करेंगे, तो हम सहयोग करेंगे और अगर सुधार नहीं करेंगे, तो हम असहयोग देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. M. S. SWAMINATHAN (Nominated): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. I think, starting with you, a large number of very valuable suggestions have been made both to handle this problem in the short-term and also in the longer term. I have been here in this House for the last five years. Almost every year, in the month of April-May, we have this discussion on foodgrains storage, foodgrains spoilage in Punjab and so on. This is but natural because only the magnitude of the problem is increasing year by year.

Mr. Vice-Chairman, Sir, when we became independent in 1947, the country was producing six million tonnes of wheat. This year, Punjab alone has over 17 million tonnes and Madhya Pradesh has 8-10 million tonnes. Procurement in Punjab alone is about 12.5 million tonnes. I said that the whole country was producing only six million tonnes in 1947. Now, Punjab alone provides double for the Public Distribution System.

Therefore, Mr. Vice-Chairman, Sir, we need enduring solutions, not merely *ad hoc* and temporary solutions. They are very important. Right now, we need many steps as you suggested. But, I think, we should now find a more enduring solution to the problem.

Sir, other countries have similar problems like Canada, Australia, etc. which are major wheat exporters. They have the Canadian Wheat Board and the Australian Wheat Board. They do two things. One is, there is a high degree of coordinated action. There is also anticipatory action. There is coordination among various Departments and anticipatory proactive action, not the post-mortem action. So, we need a structure today if we want to see that this kind of problem is not continuing to plague us. I would like to suggest for the consideration of the Government and the Minister that we need a National Foodgrains Management Board which should consist of all the players. It relates to only post-harvest management, not production side at all. Once the grain is harvested, the processing, storage, marketing and distribution, PDS and so on will be managed by this Board. It includes post-harvest handling, storage, movement, marketing and distribution. I would like to suggest that this kind of a board, namely, National Foodgrains Management Board, may confine itself to the commodities which are included in the National Food Security Bill, namely, nutri millets like bajra, jower, makka, ragi and so on, and wheat and rice, the only grains which are included in the National Food Security Bill. It can also be a virtual Board. It can be a 21st century organisation. It is not necessary to have a huge building, a huge number of staff and so on. But it should consist of all the major players starting with the FCI, Jute Board, Railway Board, Surface Transport Ministry, Warehousing Corporation and the private sector which is also becoming very important. I have seen it in Punjab where I am going the day after tomorrow. Every year I go there to study the storage problem in Punjab and Haryana. It is an exhilarating sight what I call ecstasy and agony. 'Ecstasy' in the sense what our farmers are doing, that is, the grains coming like gold, and, at the same time, how we are storing them gives you the agony. It is important that we involve the private sector, the Grain Storage Institute and scientific institutions like the CFTRI and so on. It must be a coordination and proactive planning and action programme. I think, this kind of a coordinating body is required. Since the FCI is mentioned—I have gone through the process—in the 1960s, I can say, there would not have been any Green Revolution had the FCI not existed. Because for the farmer, ultimately, it is

[PROF. M.S. SWAMINATHAN]

procurement at remunerative prices which is the greatest incentive. They are producing more because the Government is also procuring at a fairly reasonable price, thought not at the price recommended by the Farmers' Commission. But it is going up to that level. Therefore, we should develop this particular Board and a national strategy starting with what you have suggested about storage at the farmers' level, incentives for the farm level storage, farm level silos and rural godowns which already exist. Mr. Venkaiah Naidu, when he was Minister, he took interest in the Rural Godowns Scheme. Then a National Grid of ultra modern grain storage should be there in all parts of the country so that grains can be moved at a very short notice.

Sir, I may conclude by saying that we are discussing it every year and we are all feeling sorry that the grains are rotting. Every day I get a call from the media requesting me to talk about the grain storage problem, the losses and so on. We must, as a nation, find a more enduring and permanent solution. The solution is to have a structure. You look at it in a proactive way. You look at the problem. They wouldn't think of the gunny bags in the month of April. They think of the gunny bags in the month of October-November when the crop is sown. Now, we need a body which can do it. Thank you very much.

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. It is with a deep concern about the food situation of the country in the coming years, I participate in the Short Duration Discussion on the wastage of foodgrains in the country due to non-availability of adequate storage houses. We all know that still our country is experiencing food insecurity and this is not only just related to economic barriers to access food but also social barriers. Our country had earlier witnessed large-scale famines which we had overcome after struggling for several months or years. Those famines were mainly because of low level of agricultural production that was inordinately dependent on changing monsoon and extremely unequal distribution of land and food. With some land reforms, implementation of Green Revolution, improved irrigation facilities which, in turn, enhanced foodgrain production and improved distribution through the Public Distribution System, we achieved self-sufficiency to some extent in agricultural production and the danger of famine in the post-independent India has been averted. But still today, when we achieved substantial production in agriculture, the number of people who go to bed hungry has not been reduced. The gloomy

situation presently existing in the country might not be because of low agricultural production or failure of monsoon, but because of failure of post-harvest infrastructure, like shortage of cold storage chains, transportation and management of stored grains, as stated by my hon. colleague, Prof. M.S. Swaminathan. It was warned two years back when 61,000 tonnes of foodgrain had rotted in the year 2010, and an assurance was given by the Government that the storage capacity would be increased in the coming years, but the story of wastage of agricultural production continues unabatedly. The hon. Minister had also informed last year that the storage capacity would be increased to 15 million tonnes through public-private partnership and silos with a capacity of two million tonnes. Through the public-private partnership, the scheme of construction of warehouses had been implemented by the Government in 2008. Under this scheme, it was proposed to build godowns under the Seven Year Guarantee Scheme. The FCI also sent a proposal to the Government for fund allocation for creation of about 45 lakh metric tonnes capacity. Therefore, I urge the Government to give more importance to construction of warehouses in sufficient number, at least one in each district and further the open storage system should be abolished. If needed, it should be only on temporary basis covered with waterproof tarpaulin and the time for open storage of certain food grains like paddy and wheat should not exceed one month. The Government should also introduce a separate budget system for agriculture and animal husbandry on the line of the Railway Budget and the General Budget. Nearly 70 per cent of country's population is engaged, directly or indirectly, in agriculture and therefore importance should be given for enhancing post-harvest infrastructure facilities. The absence of scientific and modern technology in storage management in the Food Corporation of India's godowns is another major reason for wastage of food items. Besides building additional storage capacity, steps should be taken for upgradation of the existing State-owned warehouses. Since most of the warehouses owned by the State agencies are over 15-20 years old, hence they need upgradation to contain the wastage level. Therefore, I urge upon the Government to concentrate more on the development of storage houses in the country. In Tamil Nadu, when our leader Kalinger was the Chief Minister of Tamil Nadu, he introduced hundreds of 'Ulavar Santhai', that is, farmer's santhai, where each santhai has a cold storage to store vegetables. Such a scheme can be introduced in the whole nation. This scheme should be introduced by the Central Government with full funding. Thank you.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion on the problem of foodgrains storage in the country. I thank my leader, Shri Mangala Kisan, for giving me this opportunity to speak on this subject. When India is self-reliant in foodgrains and when we are discussing the problem of food storage in the country, the BPL families are starving. They are not getting a square meal a day. I really feel sorry for them. What is the reason behind it? We are not able to take a correct policy on demand and supply for proper planning and for proper distribution of foodgrains, even after 65 years of our independence. It comes to my mind that being a welfare State, we have not provided food security to the people of India even after 65 years of our independence. Now, where does the problem lie? What is the reason that people are starving? We should find out that first. And what are the causes for poverty in the *'grama'*, that is, the villages? What are the reasons for poverty because of which terrorism, Naxalism and Maoism are growing day by day? And this has become a stress to the nation. Sir, we should remember the words of the Father of our Nation, late Shri Mahatma Gandhi. The Father of the Nation told about *Gram Swarajya*. We observed the Sixtieth Anniversary of this august House yesterday. I think 93 and 94 or 95 Amendments have been made to strengthen the local self Govt. but we are not touching the grama and find out what the root-cause of poverty in villages is. planning should come out of that. Sir, I started my career from the 'Gram Panchayat level. I was, first, the Sarpanch and then became the President of the Zilla Parishad. And I say, with regret, that our planning has not touched the villages. We have to analyse what the proper reason for poverty there is. Sir, the FCI created 69.07 lakh tonnes storage capacity under Seven Year Guarantee Scheme in 2008. The CAG had serious objections as some capacity in Andhra Pradesh remained unutilized.

(THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) in the Chair)

The Report of the Working Group on Foodgrains, Balancing Demand and Supply during Twelfth Five Year Plan, has observed that the storage capacity being created under the Guarantee Scheme may not be fully utilized during the entire period. Sir, private entrepreneurs are not willing to lease out their warehouses to the FCI because they do not vacate the same after the period of the Lease

Agreement and various other reasons. As a result, due to lack of godowns, grains are rotting. The rains may come in June which would destroy the stocks. Sir, damaged paddy is selling at Rs. 620 for branded alcohol. Sir, I would say in this context, my hon. Leader, Shri Naveen Patnaik declared that BPL families will get rice for Rs. 2. They are getting it. And APL families in KBK districts are also getting rice for Rs. 2. **...(Time-bell rings)...** Sir, I am concluding. Sir, will the Government distribute grains among the poor before the damage of foodgrains which are stored for more than two years? Sir, I want to know, through you, how many types of authorities concerned are verifying FCI godowns in a year. I propose that Government should have FCI godowns in each district of the State. Sir, one pertinent point is there. **...(Time-bell rings)...** Sir, I am going to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): All right, please sit down. You have already taken more time.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: Sir, it is a pertinent point and I want to know from the Minister. Organisation of agricultural farmers should be organised from Gram Sabha level to Block level, District level, State level, under the umbrella of a Central level organisation. Thank you.

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to present my comments on the on-going discussion on the problems of food storage system. I appreciate the hon. Members who have brought this matter for discussion in this august House. Till recently, food storage system of India has been under attack, not only by the political parties and social organisations, but by the courts also, and even by the Apex Courts. The Supreme Court of India has passed strictures against the Government policy of storage system, and it went to the extent of saying that the wastage of grains due to paucity of space may be distributed freely to the poor who go to sleep with hunger. Sir, besides this,—as also in a reply to this august House, even today—nearly 16,386 tonnes of grains and—in a written reply in the same august House, not today—77,000 tonnes of wheat has been rendered unsuitable for human consumption during the last three years due to pest attack, leakages in godowns, spillage and waste during handling and exposure to rain. Sir, I would like to know from the Ministry, what steps have been taken to contain this precarious situation. Sir, the food stocks are expected to hit the 75 million tonnes mark. The storage

[SHRI N. BALAGANGA]

facility of FCI is 63 million tonnes, which is 12 million tonnes less than the expected stock. Sir, the present off-take for the PDS is about 53-55 million tonnes and the level of distribution will not clear the stocks fast enough to accommodate the fresh arrival or the fresh procurement. Sir, Punjab and Haryana contribute 70 per cent of the nation's foodgrain basket. There also, due to lack of proper storage facility, there may be precious loss of foodgrains. Nearly 84 metric tonnes of grains will be wasted or damaged. Sir, the Planning Commission has recommended construction of silos on PPP mode. I would like the hon. Minister to enlighten us the response of your Ministry towards this recommendation. Sir, FCI has agreed to construct silos in 10 States. I would like to know from the hon. Minister whether the work has been started. Sir, I understand that some States are asking the Central Government to export foodgrains. I would like to know what the Government's stand on this. Thank you.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important subject.

There is no doubt that management of foodgrains storage by FCI is a big failure in the country. Foodgrains estimated to peak at nearly 750 lakh metric tonnes by end of this month and record production of 252 lakh tonnes of production and nobody knows how FCI is going to manage this huge stock. As per one estimate, nearly 25% of grains go waste in the absence of proper foodgrain storage facilities.

The first point I wish to make is, the Government has initiated to build modern storage infrastructure with the help of the private sector. One recent project, arranged by the World Bank's International Finance Corporation, recently added 50,000 tonnes of modern silo storage capacity in Punjab. The facility was built and will be operated by a private company and the Government set storage price for a decade, guaranteeing the company a return on its capital. So, why cannot such PPP models taken up for construction of modern silos? I would like to know the number of such proposals from my own State Andhra Pradesh and the capacity addition that they are going to add. Even the experts say that the public-private partnership model to build silos is economically viable if storage losses exceed 2.1 per cent annually which is far below current loss estimates. So, it is better to have silos on PPP mode.

The second point I wish to make is the problem of shortage of bags that FCI is facing to keep foodgrain storage. Sir, earlier Government permitted to use plastic bags for storage of foodgrains. This year it banned plastic bags saying they are not environmental-friendly. But, there is a severe shortage of jute bags. So, I would like to know how the Ministry is planning to supply jute bags for storing foodgrains.

Thirdly, Supreme Court had directed the Government to release about 25 lakh tonnes of grains to feed the country's poor population. The government is citing high transportation costs. So, I would like to know whether any consultations have been held with State to share, at least, 50% of costs to which they readily agree for supply of foodgrains to poor, so that twin objectives can be achieved i.e., providing food to poor and reducing pressure on FCI with regard to storage of foodgrains.

Fourthly, Sir, the Government had earlier sanctioned construction of a capacity of 150 lakh tonnes storage sites, but only a meagre 0.1 per cent of the project has come into existence. I would like to know the reasons behind this pathetic performance.

Sir, FCI is failing very badly in coordinating with the Railways to get rakes for transportation of foodgrains during the peak Kharif procurement in March, April and May and Rabi procurement in September and October. Bulk procurements are coming from Andhra Pradesh, Punjab, Haryana and Tamil Nadu. So, I would like to know from the hon. Minister how is he going to improve the coordination between FCI and Railways not only for procurement of foodgrains but also distribution of the same to other respective areas through PDS. And, what plans Ministry have to develop modern facilities in FCI such as temperature control mechanism for storage of foodgrain, tracking transport movement of foodgrains online, putting storage areas under CCTV surveillance, etc. And, how much Budget Ministry has earmarked for modernisation of FCI during the current year and also in the 12th Plan.

The next point I wish to make is, there is lack of commitment in the officials to store foodgrains. The corrupt FCI depot operators sell a portion of stored grains in the black market and then intentionally allow a portion to rot and cover up the illicit sale by over reporting the wastage. If there is lack of commitment on the part

[SHRIMATI GUNDU SUDHARANI]

of officials, whatever you do, it goes into drain. So, I would like to know from the hon. Minister how is he going to address this serious problem which is coming from within.

Finally, I would like to know whether the Ministry has ever thought of a decentralized model of food storage for the country to reduce the cost of transporting foodgrains and the need for storing them for long by spreading food cultivation uniformly all over the country. Through this, the Government will not only save a substantial amount of money that goes into warehousing and reduce the time required for distribution but it can also ensure that the grains are actually reaching the beneficiaries. If so, the details may be given. If not, the reasons for not giving impetus to this issue.*

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Yes, that is the best part of your speech. Thank you. ...*(Interruptions)*... Smt. Renukaji wants to go early; she can speak now.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I have an appointment and, hence, I would like to speak early. Sir, I am really grateful that I have been given this opportunity to speak and I want to thank all my respected colleagues here for indulging me and letting me to speak on this vital issue.

Sir, all of us have been addressing these issues repeatedly over the years. As Mr. Swaminathan has rightly pointed out, it is time for us to look at issues and think out of the box and in the traditional ways. Firstly, the priority should be given to crop planning. We do not do crop planning. A lot of farmers do what is known as 'copy cat farming', as a result of which we have surplus grains. I do not think we should complain about the problems of plenty, because today we can afford to feed our nation across the board. For us, even if the hectares of land have not increased, it is because of the availability of better quality seeds, and because of more awareness on using technologies, that we are able to produce so much of foodgrains.

The States like Assam, which we considered as sleeping giants, after putting in one lakh tube wells have come in a very big way into production of rice. Yes, I agree with Mr. N. K. Singh when he did say that inter-State barriers should be

* English translation of the orignial speech delivered in Telgu.

lifted for the movement of foodgrains so that it facilitates each State, which will be much more economically viable.

As for thinking as to what we can do to solve the storage problems, we really have to invent newer ways. You have to take into confidence the Gram Panchayats so that they can lease the land from 30 to 50 years, or even 99 years, and ensure that under NREGS we construct assets in the form ot storage facilities. Agencies iike NABARD always predict in the annual reports how much storage is required, whether cold storage or dry storage. Newer technologies, such as irradiation, should be used. It is completely indigenous. Countries like Israel have been using irradiation over the years, which is a value addition. This removes micro-organisms which causes the rotting of grains. This prevents that. It does not alter the taste and does not hamper reproduction in terms of seed value. Now, this is something you can think of using. The Centre is giving huge subsidies and direct grants. Because of lack of awareness of what irradiation is, farmers are not using it. Fruits, meat, pouty, pisciculture, eggs and everything can be irradiated whereby the shelf-life of the product increases. I think, each Member of the Parliament should also talk to your lead banks, in your respective districts, that you have adopted in this august House, and the lead banks must be made to come forward to build storage in which the farmers' grains can be stored; against which, credit can be given to the farmer to facilitate him to purchase the seeds and also to meet with his private requirements of whether it is getting girls married or whatever it is.

Sir, along with that, there should be investment in post-harvest technologies. Every one is talking about hunger, and not understanding that lack of nutrition and anemia starts in utero. कुपोषण कोख से शुरू होता है और इसकी awareness is not about giving Mid-day Meals or something like that. कितने लोग हैं इस हाउस में जिन्होंने पिछले पांच साल में तीन साल के बच्चे को खाना खिलाया, यह मुझे आप सुनाइये। कोई भी तीन साल का बच्चा या पांच साल का बच्चा 200 ग्राम या 100 ग्राम एक टाइम पर बैठकर खाता नहीं है। There has to be the three 'As'—availability, affordability and accessibility of nutrition, which means, you have to fortify the five things in this country, namely, sugar, oil, rice, wheat and salt. All these five products should be fortified, so that what little goes in, gives them supplementary nutrition. It should be accessible to children who want to access food several times over a period of the day. They can't sit for one meal; sit there and eat it because they are human

[SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY]

beings. Children's behaviour pattern is that of distraction, game and fun. They keep eating and coming back and wanting more. So, you have to look at that realistically.

Sir, someone was objecting to the FCI's purchasing grains. Please do not stop that. It is just the lifeline that we, as farmers, depend on. When we give you a bumper crop, bad enough, we lose everything when the rains are not there, when there is excess rain. Every other factor in environment hurts us. When we produce good grains, even then we cannot wipe out our debts because we don't get a remunerative price. That is the market economics. Someone was asking about raising the Minimum Support Price. आप जितनी मिनीमम सपोर्ट प्राइज बढ़ाते जायेंगे, उतनी copycat farming होती जायेगी। We have to now do crop planning, where you identify sectors which will be able to grow pulses, which will grow oilseeds, which will grow rice and paddy, and make sure that the remuneration is given to those farmers, that our storage facilities and our export policies are able to have a swift response system whereby we can do that. **...(Time-bell rings)...** Sir, thank you so much for indulging me and giving me this opportunity. This is merely the tip of the iceberg. Food processing is an industry that has not taken off in India as it should have. And if we encourage food processing, right from the micro-finance women's units, at the district level, to the macro-level industry, it will help our farmers. Food processing is not a bad word. There should be fortification of food, clear labelling and identification of micro-nutrients. Not just for children, India has a huge growing population. All of us are going to be elders, and we need to have micro-nutrient supplements, which have to be used by all of us in India. So far, that has not been done. There is very little vitamin D; there is no clear labelling of food, what is safe for children and what is safe for elders. There is a lot of commercial exploitation that is taking place. If this is monitored, it will help. If the Panchayats can give land on lease, the land asset remains with the Panchayat; if, under the Corporate Social Responsibility, we can invoke industry to come forward, which would get advantages of investing in backward areas, if all this, we dovetail and use, we can find solutions. I think, it is time for this House to rise to the occasion and come forward together, not on political lines, but as people who care for this nation. Thank you very much, Sir.

5.00 P.M.

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देश में खाद्यान्न की समस्या के भंडारण पर चर्चा कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से यह समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। देश को इसके कारण भारी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इस देश में कृषि उत्पादन वृद्धि में इसके कारण बाधा आ रही है। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मेरे पूर्व आदरणीय सदस्य श्री शान्ता कुमार जी ने इसकी शुरूआत की है और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं यहां कुछ बातें कहना चाहूंगा। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं, जो हम से कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत आगे हैं और वे हमसे चार गुना ज्यादा उत्पादन करते हैं। वहां पर रख-रखाव और मार्केटिंग की कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, परन्तु हमारे देश में वह विकट समस्या बन गई है। आज हमारे देश में सरकार ने हरित-क्रांति के माध्यम से या किसानों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर, एक वातावरण बनाने का प्रयास किया है। उसके कारण कृषि उत्पादन में विशेषकर गेहूं, चावल आदि में वृद्धि हो रही है। एक समय था और आज भी है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, दूसरे नम्बर पर हरियाणा में होता है, पहले मध्य प्रदेश कहीं पीछे हुआ करता था, लेकिन इस दौर में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पंजाब, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार किसानों को प्रभावित करने के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की हैं। कृषि उपज के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, पूंजी निवेश करने वालों को ब्याज की दरों में छूट दी है और जो किसान गेहूं का उत्पादन करके सरकार को देगा, उसको सौ रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की भी व्यवस्था की है। इससे प्रभावित होकर किसान अत्यधिक मात्रा में गेहूं सरकार को बेच रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम लागू किया है। जिन-जिन किसानों ने गेहूं बोया, उनका पंजीयन किया गया और पंजीयन करने के बाद उनके मोबाइल नम्बर नोट किए गए। किस किसान को किस दिन गेहूं बेचने के लिए आना है, इस व्यवस्था से सबको SMS किए गए। यह व्यवस्था लागू करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने फरवरी, 2012 से ही केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क किया, बल्कि जनवरी से ही किया था। उनको अनुमान बताया था कि इस बार मध्य प्रदेश में इतना गेहूं पैदा होगा और हम आपको इतना गेहूं देंगे। आप उस गेहूं को समय पर उठाएंगे और उसको रखने के लिए हमें बोरियों की व्यवस्था भी करवाएंगे। केन्द्र सरकार ने इसकी सहमति भी दी और यह तय हुआ था कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को नवम्बर माह में 1,44,170 गठानें बोरियों की उपलब्ध कराएगी। उसके अनुसार फरवरी माह में 75,010 की बात हुई। पहले तीन फरवरी को और फिर पन्द्रह फरवरी को 50,050 की बात हुई, कुल मिलाकर हमें 2,69,230 गठानें चाहिए थीं। केन्द्र सरकार की सहमति के अनुसार हमने 478.75 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के खजाने में जमा कर दिए। उसके बाद यह तय हुआ कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदकर, उसको रखने की दृष्टि से अप्रैल माह के अंत तक 88,000 बोरियों की गठानें उपलब्ध कराएगी। परन्तु

[श्री थावर चन्द गहलोत]

दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल 17,000 बंडल ही उपलब्ध कराए गए। मध्य प्रदेश के ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): थापर जी, आपकी पार्टी से बोलने वाले और तीन स्पीकर्स हैं, इसलिए पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, यह मध्य प्रदेश का बहुत इम्पोर्टेन्ट और गंभीर मामला है, इसे उठाने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): बाकी लोगों को भी टाइम देना है, take two minutes more.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैंने इसीलिए बहुत सारी इधर-उधर की बातें बताई ही नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): ठीक है, आपको दो मिनट ज्यादा देते हैं।

श्री थावर चन्द गहलोत: ठीक है। केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से जो वादा किया, उसको निभाया नहीं है। केंद्र की सरकार ने वह वादा किया था कि वे एफ.सी.आई. के माध्यम से प्रति सप्ताह 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाएंगे, परन्तु उसको भी नहीं उठाया है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को बाध्य होकर, केन्द्र की सरकार के पास एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन, चार-चार बार आना पड़ा, आग्रह करना पड़ा, लेकिन आग्रह करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। हमने कहा कि आपने जूट की बोरियों में गेहूं रखने का बंधन डाल रखा है, हमको उसमें छूट दे दो, हम प्लास्टिक की बोरियां अरेंज करके उसमें भर देंगे, परन्तु यह सब भी नहीं किया है। पिछले तीन, चार वर्षों से आप और हम सब यह देख रहे हैं कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि गेहूं को सड़ाने की बजाय गरीबों में बांट दो, लेकिन वह भी नहीं बांटा जा रहा है। देश में चारों तरफ से टी.वी., दूरदर्शन और समाचार-पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि 58,000 करोड़ रुपये का गेहूं सड़ाया गया। यह सब हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम योजना बना रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो दीर्घकालीन योजना बन रही है, वह तो बन रही है, परन्तु यदि कोई कार्यवाही तत्काल की जा सकती है तो वह यह हो सकती है ...(**व्यवधान**)... सर, हमारा टाइम है, मेरा आपसे निवेदन है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): मैं क्या करूं, आपकी पार्टी ने तीन नाम और दिए हैं।

श्री थावर चन्द गहलोत: हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार से यह मांग की, यह अनुरोध किया कि हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को हम जो गेहूं बांटते हैं, वह केंद्र से, एफ.सी.आई. के माध्यम से और कहीं से आता है, इसलिए हमारे पास यह जो खुले में स्टॉक पड़ा है, इसका कंट्रोल डीलरों को देने की अनुमति दे दी

जाए। यदि हम उनको तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच महीने का इकट्ठा गेहूं दे देंगे, तो यह जो भंडारण की समस्या है, इसमें कुछ राहत मिलेगी और गेहूं सड़ने से भी बच जाएगा, परंतु केन्द्र की सरकार इसकी भी अनुमति नहीं दे रही है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): पांच मिनट की जगह आपके आठ मिनट हो गए हैं। मैं क्या करूं? You have to adjust your speech accordingly. आपकी पार्टी के तीन स्पीकर्स और हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके आठ मिनट हो गए हैं, आप इसको खत्म कीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गेहूं बाहर से आता है, वह बाहर से भेजने की बजाय, उनके लिए उसी राज्य से देने की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे लाने, ले जाने का जो खर्चा है, वह बच जाएगा और सरकार का एफ.सी.आई. गोदाम में इसको रखने का जो खर्चा होता है, वह भी बच जाएगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि मार्किटिंग की जो समस्या है, उसके समाधान के लिए यह किया जाए कि जो किसान उत्पादन करता है, आप उस किसान को ऋण अनुदान दे दें। वह स्वयं अपने खेत पर वेयरहाउस बनाएगा, उसको रखेगा और उसके बाद सरकार उनसे यह गेहूं सुविधानुसार लेने की व्यवस्था कर लेगी। ऐसा करने से सब ठीक होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है, इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्य मंत्री ने केंद्र की सरकार से जो मांग की है और केंद्र की सरकार ने जो सहमति दी है, जो वादा किया है, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें, गेहूं सड़ने से बचाएं, किसानों को लाभ पहुंचाने में सहयोग करें और गरीबों को संरक्षण देने का काम करें। धन्यवाद।

श्रीमती माया सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की स्थिति का जो वर्णन किया है, हम सभी मध्य प्रदेश वासी स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हैं।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, दूसरे सदस्य भी स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): सभी सदस्य स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हैं, I also support.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Thank you, Sir.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Andhra Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, this is an essential discussion on storage of essential commodities, that is, foodgrains. Prof. Swaminathan was mentioning about the customary debate of April-May on this issue. For me, I appreciate the gesture which will be much

[SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU]

MORE useful for making out a countdown for the food procurement, storage and foodgrain movement. I come from a State which is, otherwise, well known as *Annapurna*. Now, in my State, by our State Government, *Rythu chaitanya sadassulu*, the farmers' promotion conventions are going on. Kharif season is going to start. One month from now, we will be seeing long queues of farmers for seeds. After one-and-a-half month, we will, again, be seeing long queues for fertilizers and pesticides. By the end of August or from the beginning of September, the tensions of procurement and selling necessities of the farmers of their yield will be coming up. Then, by November-December, we will be hearing about and facing the suicide by farmers. This is the calendar going on, Sir. Based on this backdrop, Sir, I earnestly submit a few points for the consideration of the Minister of Food Procurement and Public Distribution. Prof. Thomasji is much famous in my State. He has understood the exact problem for the last three years. My State *'Annapurna'* and also several other States, including Maharashtra and Karnataka, have been regularly facing the problem of storage of foodgrains. From the inputs available from the concerned Ministry, there is a brief mention about the Food Corporation of India. To rationalise, in 2010, the staff strength of the Food Corporation of India was reduced from 55,000 to 36,000. I am told, even I have read through, and I have seen at certain places the systematic utilisation of technological facilities and modern computerised technology by this Ministry. The tracking and proper storage recording is enabled. But the claim of hon. Minister is that the requirement of foodgrains to implement the National Food Security Bill is not likely to be substantially higher than the current allocation of foodgrains, under various welfare schemes. The scale of operation of the Food Corporation of India is, therefore, not required to expand at all signficantly. I dispute with my humble understanding, and it is also mentioned that even under the Scheme, well known as PEG, the process is just at finalising the contracts, and for the coming season, it will not be useful. Okay. But, with all these things, what is to be done? There is every necessity to ensure, to work out the yield, the harvest plan. Based on the kharif-produce plan, you have to plan for the storage capacities and arrangement of rail wagons for the mobility and movement of foodgrains.

As a second point, there is every necessity to properly plan the warehousing of the foodgrains, and the destinations for the foodgrain movement should be very shorter, i.e., within 300 kilometres.

Besides that, as mentioned in PEG Scheme, as you are going to give the entrepreneurs the assurance of 10 years' hiring, there is every necessity to

encourage the individual farmers. Those were the days when they used to have their own seeds, used to have their own backyard manure and used to have their own cow dung-pasted godowns at houses.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please conclude.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Now, those were not visible and the procurement and foodgrain storage has become a very important heart-rending thing. For that, there is every necessity to coordinate with all the Departments, including the NREGS, to have godowns at each and every major *Gram Panchayat* and cold storage facility for, at least, 100 villages. This is a must to ensure proper storage of foodgrains, to ensure proper utilization of the Food Security Act. Thank you very much.

SHRI M. P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, we are in a very paradox situation. We have got a record production of foodgrains on the one side, and, on the other side, the *per capita* availability of foodgrains is declining. According to a reply given in this House in December, 2011, 'the *per capita* availability in 2006 was 445.3 grams, but, in 2010, it was reduced to 438.6 grams.'

For the last 20 years, since we embarked on the New Economic Policy, the production is increasing but the *per capita* availability of foodgrains is reducing. The Government says that 'we have got enough foodgrains in the godowns, there is enough buffer stock, But, at the same time, they are reducing the quota of foodgrain allotment to States like Kerala. In Kerala—the Minister knows it very well—the APL quota was reduced by 85 per cent, and, till now, the Government is not ready to restore it and ensure the food security in Kerala.

I think, there is a concerted effort on the part of the Government to weaken the FCI, to weaken the Public Distribution System in tune with the Neoliberal Economic Policy. The hon. Minister, Prof. K.V. Thomas, is honest enough to concede today, as the previous speaker was mentioning, that there is no necessity to strengthen and expand the working of FCI. I think, it is for the first time in this House, in Parliament, that a Food Minister is saying that there is no necessity of expanding the FCI. What does it show? We have to see the background of the statement. The hon. Member, Shri Naresh Agrawal, mentioned about the Committee constituted by the Government with industrialists like Mr. Mukesh Ambani and Mr. Godrej to study and formulate a proposal regarding processing and procurement of

[SHRI M.P. ACHUTHAN]

food products. I feel that this Government is going in for more and more privatization in this sector. They are going to entrust the procurement and distribution of foodgrains to the private sector. Now, there is a proposal emanating from many quarters that there must be direct cash transfer instead of providing foodgrains through ration shops. What would introducing direct cash transfer mean? It would mean that we need not have a Public Distribution System, and we need not have ration shops; and you just give money to the needy. Then, the needy and the poor living Below the Poverty Line would buy foodgrains from the open market. About ten years back, we used to read that big traders were the hoarders, that they were hoarding the foodgrains. Now, big corporate houses are into retail trade in India. They are procuring foodgrains directly from the *mandis* and hoarding them. Not only that, this Government is contemplating bringing in even multi-national companies to retail trade.

Therefore, if we look at the issue in hand in the background of all these aspects, the move of the Government is not to strengthen FCI, not to procure foodgrains directly from the farmers, but to give it to the corporates and the private players. If that happens, that would be the most harmful thing for this Government to do. It will endanger food security and endanger the very existence of this country. So, we must not go in for that. We must change the policy. We must go back to the policy of strengthening the FCI and procuring foodgrains from the farmers to help the farmers as well as the consumers.

Thank you, Sir.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): धन्यवाद, वाइस चेयरमैन सर। मैं मंत्री से सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर लम्बा-चौड़ा भाषण देने की बजाय अगर कोई concrete बात सदन में रखी जाए, तो बेहतर होगा। माननीय शान्ता जी ने जब अपनी बात शुरू की, तो बहुत ही अच्छे सुझाव उन्होंने यहां सदन में रखे। उनमें से कम से कम एक-दो सुझाव तो मान कर, उनके ऊपर सरकार कोई नीति बनाये, तो हम देश के अनाज को खराब होने से बचा सकते हैं।

मुझे मंत्री जी की बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन उनका संबंध अगर किसानियत से थोड़ा-सा भी है, तो कणक का वह दाना किसान के बीज बोने से लेकर इंसान के पेट में जाने तक कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन, जब उसकी मेहनत से पैदा हुआ अनाज, जो किसी के पेट में जाना है, वह सड़ जाए, तो उसका सबसे ज्यादा दु:ख उस किसान को होता है और वह सोचता है कि मैंने यह अनाज सर्दियों में रात को जाग कर और पानी के बीच में रह कर देश के लोगों के लिए पैदा किया, पर सरकार की नीतियों के कारण यह सड़ रहा है।

वैसे, अगर मैं आपको न्यूज़पेपर्स दिखाऊँ, तो इनमें कई हैडिंग्स इस संबंध में छपे हैं, जैसे- "गोदामों में सड़ रहा है अनाज" और "भण्डारण" की आधुनिक तकनीक के अभाव से अनाज की दुर्दशा।" इन समाचारपत्रों ने जो आंकड़े दिए हैं, वे भी हैरान करने वाले हैं और सरकार को ध्यान से उन पर विचार करना चाहिए। इनमें लिखा है कि आँकड़ों के मुताबिक गोदामों में रखा पचास लाख टन से ज्यादा अनाज तीन बरस से ज्यादा पुराना है और आँकड़े यह कहते हैं कि तीन साल बाद खाने वाले अनाज की गुणवत्ता खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर यह अनाज तीन-तीन साल और साढ़े तीन-चार साल गोदामों में पड़ा रहेगा और उसको सड़ने के लिए छोड़ देंगे, तो हम किसान और अपने देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक और हैडिंग जो छपी है, वह भी बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली है कि "पुराना सड़ा, नया सड़ाने की तैयारी।" मैंने इसी सत्र में एक क्वेश्चन दिया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस चक्कर को छोड़ कर कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, केन्द्र सरकार की या राज्य सरकार की, किसान के साथ खिलवाड़ करना हम बन्द करें। चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमारा एक ही aim होना चाहिए कि हम इस अनाज को कैसे बचा पाएँ और इसको गरीब के पेट में कैसे पहुंचा पाएँ। हम इस सदन में इतने लोग हैं जिनको प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको अधिकारियों का सहयोग मिलता है। अगर 60 साल से हम देश में यह व्यवस्था ही नहीं कर पाए कि अनाज को न सड़ने दें, तो शायद और कितने वर्ष इस किसान को इंतजार करना पड़ेगा कि उसके अनाज का एक-एक दाना गरीब के पेट में जाए। वैसे एक कहावत भी है, कहते हैं कि अगर सारा माल लुट रहा हो तो आधा बांट देना चाहिए, जिससे खराब होने से कम से कम आधा तो बच जाएगा। अगर इस थ्योरी को ही आप सोच लो तो जितना अनाज सड़ने के कगार पर है उस अनाज को गरीबों में बांट देते हो तो कम से कम अपने देश के गरीब गर्व से कह सकते हैं कि मेरे देश का कोई व्यक्ति भी रात को बिना खाए नहीं सोता। अगर यह कमिटमेंट सरकार कर ले तो मेरा ख्याल है कि पैसे के आंकड़ों को छोड़कर, अनाज की बर्बादी को हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शान्ता कुमार जी ने जो उदाहरण दिया है और आपको एक सुझाव भी दिया है, अगर आप उसको भी मान लें तो हम अनाज को बचा सकते हैं। आप एक-एक महीने का अनाज देते हैं, अगर उसको साल में दो बार कर देते हैं तो इससे आपका ट्रॅांस्पोर्टेशन का, स्टोरेज का कितना खर्चा बचेगा, उसका भी उन्होंने पूरा हिसाब आपको बता दिया है।

सर, मैं एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस चिंता को देखते हुए कि देश का अनाज सड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको एक सजेशन दिया था कि अनाज को गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन पता नहीं, जो सरकार एक नारा देकर सत्ता में आई थी,- "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ" आज वह हाथ कहां गया? कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मानकर वह अनाज गरीबों में बांट सकते हैं। मैं अपने स्टेट पंजाब का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां एक गोदाम के पास तहसील ऑफिस और एक स्कूल है। उस गोदाम में इतना अनाज सड़ चुका है कि वहां से सुरसुरी, जो अनाज को खराब कर रही है, वह सुरसुरी तहसील में भी फैल गई है और स्कूल में भी चली गई है। इस कारण तहसील

[श्री अविनाश राय खन्ना]

में न तहसीलदार बैठता है और न उस स्कूल में बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते हैं। इन सुरसुरियों से इतना आतंक फैल रहा है कि वहां का अनाज सड़ रहा है। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके कुछ सुझाव जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको कम से कम एक बार अपनाकर तो देखो। जिन देशों में अनाज कम होता है, हम इसको एक्सपोर्ट करके भी उन देशों में अपने देश का नाम कमा सकते हैं। सर, इस अनाज को सड़ने मत दीजिए, इस अनाज को संभालिए, किसान की इज्जत कीजिए और किसान का दर्द समझने की कोशिश कीजिए।

सर, लास्टली मैं यह कहना चाहता हूं कि जो किसान है, वह दो "G" के ऊपर निर्भर है, एक God और एक Government. न कभी God खुश होता है, न Government खुश होती है। हम लोग यहां चुनकर आए हैं, इस सम्बन्ध में जो सजेशन आए हैं, कम से कम उस किसान की वेदना को समझते हुए, ध्यान रखते हुए जब अपना रिप्लाई दें, तो इन बातों को उसमें जरूर शामिल कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रणवीर सिंह प्रजापति (हरियाणा): धन्यवाद, सर, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हमारे देश में अनाज भण्डारण की बहुत गंभीर समस्या है। देश के अंदर अनाज भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसकी बहुत सी मात्रा सड़ जाती है, जबकि देश के अंदर लाखों लोग भूखे सोते हैं, उनको खाना भी नसीब नहीं होता। अभी जैसे पहले भी चर्चा हुई, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया कि अनाज को सड़ने के बजाय गरीबों में बांट दिया जाए। हमें अखबारों के अंदर भी पढ़ने को मिलता है कि गोदामों के अंदर अनाज सड़ रहा है जो बी.पी.एल. कार्डधारक हैं, उनको या जो मिड-डे-मील्स के अंदर अनाज आता है, वह सड़ा हुआ अनाज होता है।

मैं हरियाणा से आता हूं, वहां बिजली की कमी है, पानी की कमी है, पानी की तो विशेषरूप से कमी है, उस कमी के लिए मौजूदा सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि हरियाणा में जो पिछली सरकार थी, उसने एस.वाई.एल. पर पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपने हक में करवाने का काम किया था। लेकिन न वहां की मौजूदा सरकार ने और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने वह फैसला लागू किया और हरियाणा को एस.वाई.एल. का पानी नहीं मिल पाया। महोदय, वहां पानी की कमी है, वहां के किसान यूरिया, डीएपी ब्लैक में लेते हें, बीज भी उन्हें ब्लैक में लेना पड़ता है। इस सब के बावजूद वहां के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, लेकिन आज हरियाणा में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, हालत यह हैं कि वहां ट्रैक्टर, ट्रॉलियों की लम्बी-लम्बी लाइनें लगी मिलेंगी क्योंकि किसानों को अपना अनाज उतारने की जगह नहीं मिलती। उनका गेहूं सड़क के ऊपर रखा हुआ है। वहां एफसीआई और हरियाणा का Food Supply Department, उनके अनाज को उठा नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं है। इसी तरह से जब पिछले सालों में आलू का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ तो किसानों को अपना आलू रोड के ऊपर फेंकना पड़ा था क्योंकि उनके पास उसे रखने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों के भंडारण की समुचित व्यवस्था करे।

महोदय, दूसरे हरियाणा में "SEZ" के नाम पर किसानों की जमीन acquire की जा रही है और उन पर Reliance जैसी कंपनियों के बड़े-बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं जिससे छोटे दुकानदारों का कारोबार बंद होने के कगार पर है। दूसरी ओर किसान को पूरी सहूलियत न मिलने के कारण और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण वे बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। महोदय, आज कृषि वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि किसानों को उनकी फसल का 1285 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो मूल्य मिल रहा है, वह उनकी लागत मूल्य से भी कम है। आज उसका लागत मूल्य ज्यादा बैठता है। इस कारण किसान निरंतर कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। इसलिए जहां हम उनके लिए अन्न भंडारण की समुचित व्यवस्था करें, वहीं सरकार यह भी तय करे कि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले अन्यथा छोटे किसान और छोटे व्यापारी बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे जिसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): श्री तरुण विजय। कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अनाज के भंडारण का मामला भारत के सत्ता संचालकों, धनी अफसरों और उनकी विश्व दृष्टि का एक कुपरिणाम है। महोदय, यह वह देश है जहां मोटर कम्पनियों को गाड़ियों के रखने के लिए कभी जगह की कमी नहीं होती, यह वह देश है जहां पर करोड़ों बोतल शराब के भंडारण के लिए कभी समस्या नहीं आई, कभी जगह की कमी नहीं हुई और कभी पैसे की कमी नहीं हुई। महोदय, यह वह देश है जहां पर 30 लाख लोग देश में अनाज होते हुए भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम भुखमरी का शिकार हुए थे और यह वह देश है जहां मार्च, 2012 में असम प्रदेश में वहां के समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ भूख से मर रहे बागीचों के कार्यकर्ताओं की खबर छापते हैं, 'The Valley of Death', 'The Plight of Tea Labourers in Assam's Bhuvan Valley' महोदय, यह उस देश की कथा है, जहां अनाज की कमी नहीं है, लेकिन अनाज को वितरित करने की व्यवस्था भ्रष्ट और अमीर, सामंती दृष्टि वाले लोगों के हाथों में है, जो शराब बनाने के लिए लाखों टन अनाज को नष्ट कर देना ज्यादा उचित समझते हैं। महोदय, यह खंडवा की कथा है, जहां 10 फरवरी, 2012 को फूड कॉर्पोरेशन ने 1100 क्विंटल अनाज राशन की दुकानों पर बांटने के लिए भेजा है, लेकिन वहां से एक पूरा-का-पूरा वैगन गायब हो गया। अनाज के सैकड़ों वैगन ऐसे गायब किए जाते हैं और जब तीन महीने बाद अनाज मिलता है तो सारा अनाज सड़ चुका होता है या जान-बूझ कर सड़ा दिया गया होता है।

महोदय, मैं उत्तराखंड से हूं। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री ने कल केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि आप हमारे यहां जितना अनाज भेज रहे हैं, उससे लोगों का पेट नहीं भर रहा है। आप 767 मीट्रिक टन गेहूं और 13,496 मीट्रिक टन चावल कम भेज रहे हैं। इतनी बड़ी कम मात्रा में आप उत्तराखंड के गरीब लोगों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको

[श्री तरुण विजय]

चावल और गेहूं भेज रहे हैं। वहां पर कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री यह चिट्ठी थॉमस साहब को लिख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 25,570 मीट्रिक टन गेहूं और 16,928 मीट्रिक टन चावल भेजने की तुरन्त व्यवस्था करिए, लेकिन सरकार कहती है कि हम यह सड़ा देने के लिए तैयार है, हम नष्ट कर देने के लिए तैयार हैं। इधर आप देखिए, गरीब लोग दिल्ली के स्टेशन पर और सराय रोहिल्ला से मुर्शिदाबाद और गुवाहाटी के स्टेशनों पर जूठन बटोर कर पेट भरते हैं। अभी कोई चले और दिल्ली के फुटपाथों पर देखे कि लाखों लोग किस प्रकार फुटपाथ पर रहते हुए पटरियों के किनारे गिरा हुआ भेजन बटोरते हैं और उसे खाते हैं। यह वह देश है, जो चन्द्रमा पर अपना उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों में दुनिया का सबसे भूखा देश माना गया है। यह वह देश है, जहां पर सबसे ज्यादा 46 प्रतिशत कुपोषित बच्चे रहते हैं। यह वह देश है, जहां पर लगभग 7 प्रतिशत लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार होकर जीने पर मजबूर होते हैं। उस देश में 2012 में आज यह संसद चर्चा कर रही है कि अनाज को नष्ट होने से बचाने के लिए बोरियां लाई जाएं। जब धनी लोगों का या शांति निकेतन और फ्रेंड्स कॉलोनी में कोई काम होता है, तो उनकी सीमेंट की बोरियां बचाने के लिए कभी कोई भंडार की कमी महसूस नहीं होती, उनके लिए सीमेंट मिलता है, लोहा मिलता है, उनके लिए शराब मिलती है, उनके लिए हजारों गाड़ियां पार्क करने की जगह बनाई जाती है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, लेकिन जैसा स्वामीनाथ जी कह रहे थे कि अप्रैल में अनाज नष्ट हो रहा है और बोरियां लाने के बावजूद आप उसको बचा नहीं सकते, तो यह चर्चा अप्रैल में क्यों होती है, यह सरकार पूरे एक साल तक क्यों सोती रहती है?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please conclude it now.

श्री तरुण विजय: क्या उसे पता नहीं होता कि इस समय पंजाब से सोना उगलने वाली धरती का अनाज आएगा, जिसको इकट्ठा करने के लिए भंडारण की आवश्यकता होगी? यह भारत के गरीबों के साथ * करने वाली सरकार है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): तरुण जी, कन्क्लूड करो।

श्री तरुण विजय: यह भारत के दीन-हीन और भूख के शिकार लोगों के साथ * है, जो भूख के साथ खिलवाड़ करती है।

महोदय, व्यवस्था होनी चाहिए कि भंडारण की व्यवस्था पूरे एक साल पहले से शुरू हो और जो अनाज नष्ट करे, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि नष्ट न करके गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाए, उन अधिकारियों की एकाउंटिबिलिटी निश्चित की जाए और देखा जाए कि उसके बाद एक भी व्यक्ति भूख का शिकार न हो। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): श्री राम कृपाल यादव, सिर्फ पांच मिनट। सबके लिए पांच मिनट का समय है, आपके लिए भी पांच मिनट हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): सर, आपका प्यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): प्यार ज्यादा है, लेकिन टाइम पांच मिनट ही है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, इसी तरह से अपनी निगाह मेरे ऊपर रखिए, काम चलेगा।

सर, यह बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, जो देश के सामने एक विकट समस्या पैदा हो गई है। यह जो 2011-12 का आंकड़ा है, इसके अनुसार देश में अनाज का 25 करोड़ टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन उपलब्ध भंडार में जो भंडारण की क्षमता है वह 10.87 करोड़ टन की है, यानी मात्र इतना अनाज रखने की क्षमता है। यह चिंता का विषय है। खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि पिछले वर्ष पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 70 हजार टन गेहूं उचित रख-रखाव के अभाव में खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। विडंबना यह है कि एक तरफ अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। इस देश में करीब 35 परसेंट आबादी ऐसी है, जो भुखमरी और गरीबी से जूझने वाली आबादी है तथा लोग भूखे सो जाने पर बाध्य हैं। सरकार को ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए। Markfed द्वारा खरीदे गए गेहूं की करीब 2 लाख बोरियां खुले आसमान के नीचे रखने के कारण वह गेहूं सड़कर खराब हो गया। एक ज़माना था जब अनाज के मामले में हमारी आत्मनिर्भरता कम थी। इस देश के किसानों ने मेहनत करके, मजदूरी करके और अपना खून-पसीना लगाकर देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाई, लेकिन उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको निराशा हो रही है तथा उनके द्वारा उपजाया गया अनाज सड़ रहा है। इसलिए सरकार को इन किसानों की चिंता करने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में कुल भंडारण की क्षमता मात्र 76 प्रतिशत है और बाकी 24 प्रतिशत अनाज भंडारण के अभाव के कारण सड़ जाता है। हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन लगभग 25 प्रतिशत है। अगर प्रबंधन ठीक हो, तो इस आबादी को यह अनाज पहुंचाया जा सकता है और इससे गरीबों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण एक ओर अनाज सड़ रहा है और दूसरी ओर गरीब लोग परेशानी की हालत में हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में तीन तरह की संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से हम अनाज को स्टोर करते हैं - FCI, Cenral Warehousing Corporation & State Warehousing Corporations के माध्यम से, लेकिन मैं समझता हूं कि ये नाकाफी हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि ब्लॉक लेवल पर गोदाम बनाकर खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था हो सके। केवल गेहूं और चावल ही नहीं, बड़े पैमाने पर साग-सब्जी का जो उत्पादन होता है, वह भी बर्बाद हो जाता है और बिचौलियों के माध्यम से उनका शोषण होता है, क्योंकि भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण औने-पौने दामों पर बिचौलिए लोग किसानों से कम मूल्य पर अनाज लेते हैं और उसे अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन

[श्री राम कृपाल यादव]

करूंगा कि निश्चित तौर पर आप ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की व्यवस्था कीजिए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके और जो किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, निश्चित तौर पर वे उससे बाहर निकल सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, चूंकि टाइम हो रहा है और आम मुझे कहेंगे कि बैठ जाइए, तो एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज पूरे देश में बोरियों का अभाव है, जबकि वास्तव में बोरियों का अभाव नहीं है। किसी न किसी तरीके से यह कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है, क्योंकि जो दुकानदार या व्यापारी हैं, वे तो कह रहे हैं कि हमारे पास बोरियां हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी बोरियों की मांग की गई है और किन-किन राज्यों में आपने कितनी-कितनी बोरियां उपलब्ध कराई हैं? जब आप जवाब दें, तो अपने जवाब में यह जरूर बताएं।

उपसभाध्यक्ष जी, तरुण विजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यह एक साजिश की जा रही है। हमारा जो अनाज सड़ रहा है, वह अधिकारियों के माध्यम से और व्यवसायियों की मिलीभगत से सड़ाया जा रहा है। जो शराब व्यवसायी हैं, उनकी यह मिलीभगत है क्योंकि जो सड़ा हुआ अनाज है, उसकी कम कीमत में बिक्री हो जाती है और मैं समझता हूं कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह एक बड़ी साजिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं एफ.सी.आई. और जो अधिकारी वर्ग है, उस पर निश्चित तौर पर सरकार को निगाह रखनी चाहिए और अपने जवाब में आपको यह ज़रूर बताना चाहिए।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि भारत का जो किसान है, आज बदहाली और फटेहाली में गुज़र कर रहा है, उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है। किसान के प्रति जो सकारात्मक भावना है, उसमें कमी आ रही है, इसलिए माननीय मंत्री जी, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। जब तक उचित भंडारण उपलब्ध नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। मुझे भरोसा है, आपने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको आदेश दिया है जो अनाज सड़ रहा है, उसे आप गरीबों में बांट दें, पर आप वह भी नहीं कर पाए। इसलिए आप एक कारगर कदम उठाइए। मुझे जानकारी है कि आपने पांच हजार करोड़ रुपए की राशि warehousing को देने के लिए या एफ.सी.आई. के और गोदाम बनाने के लिए उपलब्ध कराई है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आप इस पर ध्यान देंगे, ताकि खाद्य भंडारण की सही व्यवस्था हो सके और किसानों को राहत मिल सके, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Hon. Members, I have 3-4 more names which have been received after the discussion started. However, I am allowing them on the condition that they will speak only for two minutes. Each will speak for two minutes. Now, Mr. Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, today, we are discussing a very important topic which is directly related to the problem faced by the poor

farmers of our country. Sir, lack of storage facilities is one of the worst problems faced by farmers in our country. In our country, storage facilities are looked after by several Government agencies, for example, Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations. To a certain extent, Agricultural Marketing Board also plays a role for the storage facilities in our country.

Sir, production of crops, marketing of crops and storage facilities of crops are inter-related issues. Without marketing, farmers will not get a just price and without storage, it will not be possible for the farmers to get the market. Sir, due to lack of marketing facilities, our farmers are facing lots of problems. Farmers produces crops and middlemen are looting the money. Secondly, Sir, they are not getting the proper marketing facilities. Sir, what is the problem? What is the ground reality? We have to take that into consideration.

Sir, the Food Corporation of India looks after storage facilities in our country. But, the storage policy of the Food Corporation of India is very narrow. Sir, the Government must have some ambitious plans. The Government should take it seriously. Then, Sir, the State Warehousing Corporations also play an important role in the storage facilities of our country but, due to lack of funds and lack of budgetary provisions, the State Warehousing Corporations are facing a serious problem.

Sir, in winter season, our farmers produce bumper production of vegetables, for example, tomatoes, potatoes, gobhi, etc. But, farmers are not getting the market and there are no storage facilities also. So, they have no option. Under compulsion, they are destroying their production because they are not getting the minimum price. They are not even getting the cost of production. So, under compulsion, farmers destroy their produce. The destruction of foodgrains also is a crime and the Central Government.*

Sir, it is the duty of the Government of India to kindly look into this problem faced by our farmers. Otherwise, farmers will not get any benefit from our side. Sir, first, the Government of India must have an ambitious plan. There should be storage facilities from the Panchayat level, from the Block level, from the District level to the State level. **...(Time-bell rings)...** Sir, I am concluding.

Sir, cold-storage facility is the call of the hour. Due to shortage of cold-storage facility, our farmers destroy their produce, particularly potatoes, tomatoes

Expunged as ordered by the Chair.

[SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA]

and ghobi. Sir, the Government of India should have some ambitious plan for this. Sir, Mr. Tarun Vijay has made an important reference to my State where due to shortage of foodgrains, people are dying. Problems of Assam are known to everybody. Every year, due to floods, hectares of cultivated land are totally destroyed in our country and due to lack of storage facilities, lakhs of tonnes of produce is lost. **...(Time-bell rings)...** So, I would request the Government to kindly look into this. Our State is backward. We are already facing the flood problem. Sir, therefore, there should be sufficient storage facilities in our State also. Mr. Minister, kindly look after this problem, otherwise, farmers will not get justice.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): All right. Shri Upendra Yadav. Take three minutes.

SHRI BIRENDRA PASAD BAISHYA: Production of crops, marketing of the crops and storage facilities for the crops are also equally; important. I think, the hon. Minister will lay emphasis on this issue. Thank you.

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अनाज के भंडारण की इस समय जो समस्या है, उसमें मैं विशेष रूप से राजस्थान की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस साल राजस्थान में जो फसल बोयी गयी, वह 26.77 लाख हेक्टेयर में बोई गयी। कृषि विभाग का यह अनुमान है कि राजस्थान में 133 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। आपने हरियाणा में 60 लाख मीट्रिक टन खरीदना तय किया, आपने मध्य प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन खरीदना तय किया, लेकिन राजस्थान में केवल 20 लाख मीट्रिक टन खरीदना ही तय किया गया। उसमें से भी तक केवल दस लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। राजस्थान में जो खरीद केन्द्र बनाए गए, वे 317 बनाए गए, लेकिन इन 317 खरीद केन्द्रों पर जो व्यवस्था की स्थिति थी, जो बारदाने का अभाव था, जो जूट का अभाव था, उसके कारण किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। पूरे कोटा और हाड़ोती में, जहां पर यह उत्पादन होना था, वहां आज तक आधे से ज्यादा किसान भी खरीद नहीं कर पाए। आपने जो समर्थन मूल्य 1385 रुपए रखा था, किसानों को मजबूर होकर, क्योंकि आठ-दस दिन उन लोगों को इंतजार करना पड़ा, 1050 रुपए के मूल्य पर अपना अनाज बेचने पर विवश होना पड़ा। राजस्थान में यह जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण आज किसान बड़ा बेचैन है। कई बार तो मुझे यह लगता है कि किसान को मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है? जब आपको पता था कि इस बार जो मौसम है, वह अच्छा है, इस बार फसल ज्यादा अच्छी आने वाली है तो इस सरकार ने ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न की कि वह सही समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं करा पायी। यह इस सरकार की अक्षमता है। यह केवल सरकार की अक्षमता नहीं है, पिछले सालों में जो गेहूं सड़ा है, वह कम उत्पादन होने के बाद भी सड़ा है। महोदय, माननीय राम कृपाल यादव जी ठीक कह रहे थे कि गेहूं के सड़ने का कारण केवल

अव्यवस्था नहीं है, गेहूं के सड़ने का बहुत बड़ा कारण शराब माफिया का होना भी है। आज गेहूं को जान-बूझकर सड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि भंडारण की जो विकराल समस्या है, इसका समाधान इस सरकार के पास नहीं है। स्वयं कृषि मंत्री जी ने कहा है कि पिछले दस सालों में एफसीआई कोई ऐसी सुसंगत योजना नहीं बना पायी है, जिस योजना के कारण भंडारण की क्षमता का किसी भी प्रकार से कोई समाधान निकाला जाए। इसीलिए किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। विशेष रूप से राजस्थान में कोटा में पिछले दिनों में लगभग दो सौ करोड़ रुपए का किसानों का बकाया है, वह अभी तक नहीं मिला है। इसी प्रकार हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र का डेढ़ सौ करोड़ रुपए का बकाया भी इस समय किसानों को नहीं मिला है। इसलिए जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, वे मूल रूप से उसकी गलत नीतियों के कारण हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भंडारण की समस्या के बारे में अभी स्वामीनाथन जी कह रहे थे कि पिछले पांच सालों से लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि इतनी चर्चा चलने के बाद सरकार क्या कोई सुसंगत नीति लेकर आयी है? क्या सरकार इस प्रकार की नीति को लाने में सक्षम हुई है कि वह भंडारण क्षमता का कोई निस्तारण कर सके? आप लोगों ने सब्सिडी की बात की, एफसीआई के गोदाम बनाने की बात की, लेकिन चर्चा में से यह ध्यान में आया कि एफसीआई के जो गोदाम बनाने की बात है, उसको आप अमली-जामा नहीं पहना पाए हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसी व्यावहारिक नीति नहीं है जो इस सारी समस्या का समाधान कर सके। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, मैंने राजस्थान का जो विषय उठाया है, वह इसलिए उठाया है कि बीस लाख मीट्रिक टन का जो आपका लक्ष्य है, वह कम है। उसमें से भी दस लाख टन मीट्रिक टन लेकर आपने राजस्थान में किसानों के साथ अन्याय किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Batra. He is not there. Shri Munabbar Saleem. He is not there. Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman for allowing me to speak on grain drain. As the House knows, following the media exposure of foodgrain rotting in openstorage, in 2010, the Supreme Court ordered the Central Government to hand it out free to the poor than let it go waste. In spite of this instruction, the Central Government has been unable to improve the situation, particularly in two States, Punjab and Haryana, where most of the grain is stored and damaged, and in other areas too. As per the information, last year, 20-22 lakh tonnes of wheat in Punjab were stored unscientifically; and this year, it is likely to be more than 30 lakh tonnes. It is estimated that in Haryana too 50 lakh tonnes will be wasted and it will be going down the drain. Even the storage capacity that is considered regular, half of it is actually on plinths in the open. Recently, after the media reports that the gunny bags were in acute shortage, things started to

[SHRI ANIL DESAI]

move in the Government. They were trying to save their skin. But if the things go on like this, the situation will be very grim all over the country. Hon. Member, Prof. M. S. Swaminathan, had stated in his speech that it was just like an annual schedule programme of the Government to discuss such kinds of things in the months of April and May. Every hon. Member has expressed his concern in regard to the agriculture produce and foodgrains going waste. Wherefrom would the investment come? It has to come from the Centre which obtains most of the grain produced in the States. I appreciate that the Centre has taken steps such as increasing the budget for storage and giving loans and subsidies for private investment in this sector, but the results are not encouraging. While shortage of space is one of the reasons for the crisis, another reason is poor management of logistics of foodgrain movement. Rail rakes are often not available in required numbers and accurate estimates of requirement in different parts of the country are not made in advance. In fact, if the country could devise a way of predicting area-wise demand, some of the grain could be stored in consumption States, rather than in producer States. Totally covered storage for all foodgrain is likely to remain a dream for, at least, a few more years. Food managers would have to innovate till then. One of the deterrents for private storage investment in Punjab is low rents offered, compared to the high land cost. To overcome that, farmers could be encouraged to hold their produce for a few months by offering increased payment for delayed sale. The Indian Council of Agricultural Research has predicted that demand for foodgrain could outstrip supply by around 30 per cent by 2020. Letting our foodgrain rot is definitely not an option.

I would like to mention one more thing. The Minister of Agriculture hails from Maharashtra. A lot of idealistic speeches have been made by the Treasury Benches, but if you happen to see the plight of the farmers of Maharashtra, the situation is very gloomy. The things which are being produced in Maharashtra, are not getting markets. There are many shortcomings and these shortcomings are there because of lack of proper approach from the Government side. If you take the case of onion producing farmers of Maharashtra....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please conclude.

SHRI ANIL DESAI: ....no impetus or encouragement is being given for exports. There is no formal or regular policy on exports. These are the things which should be looked into. We should have a pro-active plan, rather than going in for

6.00 P.M.

a postmortem or holding such kinds of discussions every year. The Food Security Bill is on the anvil. That should be looked into. Shri Naresh Agrarwal was absolutely right in pointing out that the Committee which was being formed with the big names of industrialists like Ambanis and Tatas, should consist of some, agriculturists like Prof. Swaminathan and even farmers, who really toil to produce something for the country. In this way, the produce will be in our hands and it will be feeding India and the poor people of India. Thank you.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K. V. THOMAS): Mr. Vice-Chairman, Sir, today's discussion was on the problem of foodgrains storage and management in the country. Shri Shanta Kumar has started this discussion and 23 other hon. Members participated in the discussion. Shri Shanta Kumar has also handled this Department. Many of the hon. Members, including Prof. M.S. Swaminathan and Shri N. K. Singh, who have participated in the discussion, have also made their contribution in the agricultural sector in this country. Sir, I wish to start from the production scenario of the country. In 2009-10, our total production of rice and wheat was to the tune of 160.89 million tonnes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Just a minute, please. Hon. Members, after the Minister's reply, Special Mentions will be allowed to be read out.

PROF. K. V. THOMAS: Sir, in 2009-10, our production of rice and wheat was to the tune of 160.89 million tonnes, which, this year, has reached the record production level of 193.64 million tonnes. As an Indian, I am very proud because this nation, within a period of 65 years, could produce foodgrains not only sufficient for the people of our country, which total up to 120 crores, but we could also export. This year, 40-44 lakh tonnes of rice have been exported under OGL, and about 8 lakh tonnes of wheat have been exported under OGL. We should remember that 65 years back, when we got independence,—I am coming from a small fisherman's village—we had to wait for rice for the ships to come from Burma. We had to wait for the PL-480 American wheat. From those periods, we have come to a stage where we have got plenty. I know there is a problem of plenty. Sir, we have to find ways and means as to how this problem of plenty

[PROF. K.V. THOMAS]

has to be tackled. One is the issue of procurement. Shri N. K. Singh and Shri Swaminathan referred to procurement. If you look at the earlier estimates, the FCI was procuring 20-25 per cent of what we produced. From that stage, this year, our procurement is to the tune of 34-35 per cent. It is a huge procurement. In physical terms, for our Public Distribution System, we need 55-60 million tonnes. And even if the Food Security Bill, which is going to be implemented, comes into effect, it will be around 63 million tonnes. That is what I said in the case of FCI management. We didn't say that the FCI would not be modernised. But I said that there need not be any special mechanism for FCI. The FCI is getting modernized. Sir, Mackenzie has been entrusted with the modernization process of the FCI. About five years back, our strength of 55,000 was brought down to 30,000. And we have been managing with this decreased strength. But the Finance Ministry has agreed, and we have started recruitment. To this strength of 30,000, we are adding another 10,000. Step-by-step, we are going to strengthen the FCI. It has got modernized. Almost all our godowns are computerized. Sir, very often, we have been criticized for the damage of foodgrains. Still, I want to stress the point that I cannot agree with all these news reports that lakhs and lakhs of tonnes of foodgrains are getting damaged. I have stated in the House that in 2002-03 the quantity of damaged foodgrains was 1.35 lakh tonnes. It has come down to 0.03 lakh. I request the hon. Members to please verify your FCI godowns in your respective States. Please verify. We have constituted a Consultative Committee with one of the MPs as the Chairman and hon. citizens, including the media persons as members, in every State, we are going to strengthen the FCI Consultative Committee. Let the system be transparent. I don't thrust upon my data, but this is the data I have got, and I am not blaming any media. I don't criticize the media, but many of the pictures which they are projecting now are taken about five years or four years before. So,..

SHRI TARUN VIJAY: Sir, I seek your protection because hon. Minister has said that we have enough grains but then, the pictures published in the media are of the latest dates. They are taken one day or two days before. So, how can he say that no grain is being destroyed and if we have enough grains, why....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Are you yielding, Mr. Minister?

PROF. K.V. THOMAS: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Vijay, he is not yielding.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I am giving this information from my experience and my knowledge. If I am wrong, I am prepared to rectify that. But, with my experience, my knowledge, my information I am giving this information. I told you, I am not against the media. So, our procurement is to the tune of thirty-four percentage of what we are producing. So, what is the reason? Sir, within the last five years, MSP has been doubled. Many States are giving bonus and as a result, the farmers are now coming to FCI or to the State agencies. Take for example, Punjab and Haryana, it is State agencies which are procuring either wheat or rice. From these agencies we have to take it. So, a large quantity of foodgrains, earlier which have been traded by the private traders, are now coming to the State agencies. It is a question which Mr. N.K. Singh has asked: what should be the procurement policy of the Government?

श्री रणवीर सिंह प्रजापति: यूरिया का कितना रेट बढ़ गया है ...**(व्यवधान)**... आप उसके बारे में बताएं ...**(व्यवधान)**...

PROF. K. V. THOMAS: I am not against that. I am not against increasing the MSP. I am coming back to the factual point, whereby FCI has to procure more than what it needs for the PDS system. I said for the PDS system, even if the Food Security Bill is going to be implemented, it will not be more than 60-62 million tonnes. We have already procured 75 million tonnes. I agree that farmers should get a better MSP. I agree that the States should announce the bonus, but, can FCI procure the entire foodgrains of the country? Have we got the mechanism? What is the burden? My present subsidy is to the tune of Rs. 88,000 crores, and if the Food Security Bill has to be implemented, apart from the investment in agriculture, every year, we have to invest a large amount in agriculture so that agricultural production sustains. But apart from that, my food subsidy, Sir, will be to the tune of Rs. 1,09,000 crores to Rs. 1,20,000 crores. A few days back, the hon. Finance Minister said in the other House that all of us should sit together and decide what should be the mechanism of procurement. Here, it was raised that jute bags are not available. Sir, I don't want to question the management capacity of any State. But, there are certain facts which we have to accept. Every year, in the month of November-December, we, as the coordinating agency our Ministry is only the coordinating agency—sit with the DGST of the Commerce Ministry, Jute Commission and all major procuring States. We take a calculation from the States as to how many jute bags each State requires.

[PROF. K.V. THOMAS]

This year also an assessment was made. The representatives of the major wheat-procuring States—Punjab, Haryana, MP, UP—were there and the assessment was made. What was their stand? Sir, an assessment was made on 22-11-2011. What was the assessment? Sir, the Government of Madhya Pradesh gave an assessment that it is going to procure 65 lakh tonnes of wheat. These are all facts and figures. It needed around 2.88 lakh jute bales. Each bale contains 500 bags. In that meeting, the representative of Madhya Pradesh told us that out of 2.88 lakh bales, it will procure 50 per cent through private sources. It was agreed. But, after a few months, the Government of Madhya Pradesh says, 'We could not procure 50 per cent i.e., 1.44 lakh bales. So, please make arrangement for the entire quantity of 2.88 lakh bales.' There was a problem. This has to be distributed. Order has to be placed. We agreed. But, in April, the officials from Madhya Pradesh came. Later, I also talked to the hon. Chief Minister of Madhya Pradesh. They said that from 65 lakh tonnes proposed to procure earlier, it has gone up to 80 lakh tonnes. I don't blame them. And, they asked for another 50,000 bales. Sir, we have already made arrangement for distribution of bales in Punjab, Haryana, UP and MP.

SHRI BHUPENDER YADAV: What about Rajasthan?

PROF. K.V. THOMAS: I come to Rajasthan later.

Sir, in Rajasthan and Bihar, arrangement is made through the FCI. We will take care of that responsibility. I will send my officers to Rajasthan as well as Bihar and talk to them. We are finding out a mechanism. It is our responsibility i.e., FCI. We are taking care of that. But the quantities from Rajasthan and Bihar are small when compared to Punjab and Haryana. I will come back to that. We have discussed it with the Government. Our senior officers are there. We have chalked out a plan.

I come back to Madhya Pradesh. I met the hon. Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Smt. Sushma Swaraj, sat with the officers and a plan has been chalked out. Our officers are in Kolkata. The officers from the Government of Madhya Pradesh are there. Sir, UP has a problem. All this has happened because in November, 2011, the States could not properly target what they needed. Don't blame us. But, still, I have instructions from the hon. Prime Minister and blame anybody. So, we are doing our best and I am very confident that we will be able to manage.

Apart from jute, usually, we do not allow anything else. But, we allowed 20 per cent of the production in the country can use the high density plastic bags. We agreed; we are supplying. We usually don't agree that the used bags of one year or two years to be used. We also agreed to this as a special case. So, we are trying to manage the situation. Here, there are no politics, because there is a huge production of foodgrains.

In the last two-and-a-half-years, we have been in constant touch with every new emerging States. I congratulate these States–Madhya Pradesh, UP–for the steps they have taken. Because of the 'look east' policy of the Government, a lot of changes have taken place in agriculture. Productivity has gone up. We have been telling all the new emerging States to start the management of procurement.

Then, I come to the question whether we have enough storage mechanism with us. Sir, we need more. I do not say that we have got enough. Why? Sir, if it is the usual TPDS system, what I need is around 55-60 MT capacity. I have already got 63 MT with me, both capped and covered; and, under 151 lakh tonnes scheme, this March, we have got another 3 MT capacity addition. Sir, we also have had creation of smaller godowns, done by the State Governments; we sanctioned grants to 0.7 lakh MT capacity building and, recently, they have completed about 0.2 lakh MT.

Under the Gram Bhandar Yojana, 310 lakh tonnes capacity building has been allocated and 96 lakh tonnes capacity has been constructed. Under RIDF Funds through NABARD, 90 lakh tonnes capacity building has been approved. We have been telling the State Governments, "We will make use of some financial assistance either through NABARD or through RIDF, let there be smaller and medium-sized godowns with the State Governments." There is one problem in Kerala. Kerala is one of the best States in the implementation of PDS. Chhattisgarh is another State. But, in Kerala, we do not have intermediate godowns. Sir, in Kerala, straight from the FCI godowns, the foodgrains are taken to the PDS store. It is a major problem we face. To every Government there, whether LDF or UDF, we have been pointing out, "We will give assistance, but please have medium-sized godowns." We have been telling this fact to every State Government, "We give assistance, please construct medium-sized godowns." This is the situation. We have to construct more godowns.

[PROF. K.V. THOMAS]

With regard to the pet scheme of creating 151 lakh tonnes capacity, it has been planned and the construction is going on as per our plan. We will complete all the constructions under this by 2013. This is the position.

Sir, there is another question raised about restriction in the movement of foodgrains. Sir, there is no restriction. There had been some problem in Andhra Pradesh. I discussed with the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh. Now, there is no restriction in the movement of foodgrains. Foodgrains can be moved throughout the country.

Sir, coming to the PDS, I am not claiming that PDS is foolproof. But, as I said in the Question Hour, have we got any other option to feed the 120 crores of people other than strengthening the FCI and the PDS in the country? Sir, I have got a letter from a very eminent person, Prof. Gilchrist, which has been sent to the hon. Prime Minister. He had criticised the PDS sometime back. They had a survey. This survey points to an impressive revival of the PDS across the country. "In all the sample-States, with a notable exception of Bihar, there have been major initiatives in the recent past to improve the PDS and these efforts are showing results. Most of the sample households were getting the bulk, if not all of their foodgrains entitlement under the PDS, up to 35 kgs. per month at a nominal price. The days when up to half of the PDS grain was diverted to the open market are gone." About 35 professors had been criticising us; we accepted the criticism in a healthy manner. They have recently written to the hon. Prime Minister. So, why? I give the credit to the State Governments. Sir, look at the modernisation taking place in our States. In Chhattisgarh, the movement of foodgrains is monitored through the satellites. The Aadhar system is being implemented; computerisation is being implemented. Sir, we have got 20 crores ration cards in the country. Out of that, recently, it has been found out that two crores are bogus ration cards. It has been deleted. Still we have to do lot of things in the modernisation of the PDS.

Sir, my good friend, comrade Achuthan, said that we are for cash cards. We are not for cash cards. Some of the States, like Bihar, have suggested that there can be cash cards. It has to be decided by the States. Primarily, running the PDS is the responsibility of the State Governments.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Bihar): Sir, you said that the Bihar Government has suggested that there should be an alternative arrangement. But I request you that the PDS is the best system. Don't go by the advice of the State Government.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, what I suggest is, these are the issues which we have to discuss with the State Governments. Every State has autonomy and liberty.

Sir, coming to allocations, in the case of normal PDS, the off-take is around 85 to 90 per cent. As directed by the Supreme Court, we have been asked to make special allocations, and we are making special allocations. But on special allocations, the off-take is very, very small. The Supreme Court has directed to allocate 50 lakh tonnes of foodgrains under the BPL rate. Sir, we accepted the direction of the Supreme Court. But, till today, just below two lakh tonnes has gone out. It is under complete supervision of the State Governments. Sir, some of the State Governments have requested for additional allocations, and we are trying to help these States. Whichever State is coming to us, we discuss with the State Government, and we are making the additional allocations.

Sir, the last point is the point of nutrition. Sir, in the proposed Food Security Bill, it becomes the right of a person. It is not what Government gives, it becomes a right. What we have suggested for the pregnant woman is so much calories of prepared food should be given. For children, from the age of three months till they go to eighth standard, how much calories of prepared food has to be given; all these things are being given in the proposed Food Securities Bill, which gives them a right. Sir, our thrust is on the nutrition. And, more than that, the important point is that the mother is the head of the family. This is the important change made in this Bill. So, we are trying our best to see that this is done. Sir, a record production is taking place. I know there are problems; I don't claim that there is no problem. But we will discuss them with the State Governments. We are in constant touch with the State Governments. We will find out solutions. Sir, I am thankful to all the Members who have participated in the debate. With these words, I conclude.

श्रीमती माया सिंह: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मंत्री जी ने यह कहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिले। लेकिन, उसका लाभ उपभोक्ताओं को तो तब मिलेगा जब अनाज सुरक्षित रह पाएगा? भण्डारण की व्यवस्था नहीं है, जबकि मंत्री जी उससे अलग हट कर बात कह रहे हैं। इसी प्रकार, राज्य की सरकारें केन्द्रीय पूल में जिस अनाज की खरीद कर रही हैं, उसको आप उठा नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी को इन बातों का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये कुपोषित बच्चों के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, Shri Shanta Kumar.

श्री शान्ता कुमार: उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। मुख्य सवाल यह है कि भण्डारण, आपकी कपैसिटी से दो सौ-ढाई सौ लाख टन ज्यादा हो रहा है। सवाल यह है कि आप यह ढाई सौ-तीन सौ लाख टन कहाँ रखेंगे? अगर आप इसे बाहर रखेंगे, तो चूहे खाएंगे। आपको चूहे और भारत के गरीब में से किसी एक को चुनना है कि भारत के चूहे को यह अनाज खाने देना है या भारत के गरीब के घर तक इस अनाज को पहुंचाना है। ...(**व्यवधान**)... मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): It cannot be another discussion. ...*(Interruptions)*... You are the initiator, you can ask, others cannot. ...*(Interruptions)*... No, no...*(Interruptions)*... Those who did not speak cannot ask. ...*(Interruptions)*... Those who took part in the debate only can ask their questions. ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... He is asking for you also. ...*(Interruptions)*...

श्री शान्ता कुमार: सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अनाज कितना खराब होता है, हम गलत हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो गलत नहीं हो सकता। एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, सरकार को फटकारा है। यह कहा है कि अनाज खराब हो रहा है इसको मुफ्त बांट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाधवा कमेटी बनाई थी। वाधवा कमेटी ने यह कहा कि लगभग 40 प्रतिशत अनाज खराब होता है और चोरी होता है।

मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग की एक रिपोर्ट मैंने पेश की है। उस रिपोर्ट में कहा है कि एक रुपए का अनाज कंज्यूमर तक पहुंचाने में यह सरकार तीन रुपए पैंसठ पैसे खर्च करती है। इन सारी बातों का ध्यान रखकर जो मैंने सुझाव दिया है कि आप दो रुपए सस्ता दीजिए और 175 लाख टन कैपेसिटी खाली करवाइए, इसमें आपको क्या ऐतराज है? अनाज खराब करने के बजाय, चूहों को खिलाने के बजाय सस्ता देकर गरीब आदमी को देने में क्या ऐतराज है, यह हम जानना चाहते हैं?

श्री राम कृपाल यादव: सर, बस, एक क्वेश्चन। मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, जिसका जवाब नहीं आ सका। प्रत्येक राज्य में जो बोरों का अभाव है, उसको आप कैसे पूरा कर रहे हैं? इसके अलावा खास तौर पर मैंने यह भी पूछा था कि बिहार में कितने बोरों की डिमांड की गई और अभी तक आपने इस संबंध में क्या स्टेप्स उठाए हैं? सर, इन पर मंत्री जी का क्लिअर जवाब नहीं आया है।

SHRI D. BANDYOPADHYAY: I have only a short question. The point is that there is a problem of crisis of jute bags in Kolkata. The Indian Jute Mills Association has alleged that the price of jute is not being changed. The formula is of 2001 which is not being changed. That is causing a problem.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, in our nation, till now, 33 per cent of women are suffering from malnutrition. In this regard, what steps are being taken? This I want to know from the Minister.

SHRI M.P. ACHUTAN: Prof. Swaminathan has suggested an institutional mechanism for procurement. What is the response of the hon. Minister on that?

श्री थावर चन्द गहलौत: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो बातचीत की थी तथा बोरियों की गठान देने का वायदा किया था, उसमें से अब तक कितनी दीं और बाकी कब तक दे देंगे? क्या विदिन लिमिट दे देंगे?

श्री तरुण विजय: इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के हुए फैसले से क्या मंत्री महोदय सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार वह बात कही जो मंत्री महोदय के कथन से उलट है। तो क्या इस बारे में मंत्री महोदय, स्पष्ट करेंगे?

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े डिस्कशन में मंत्री महोदय ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि यहां इतने सजेशन दिए गए हैं। क्या आप इस सदन को एश्यॉर करेंगे कि सारे देश में अनाज का एक भी दाना नहीं सड़ेगा?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Whatever you can reply, you reply, otherwise, you can write to them. ...*(Interruptions)*...

PROF. K.V. THOMAS: Sir, some of the points I will answer. Shri Shanta Kumar has raised the issue of storage capacity. Sir, it is true that the covered capacity of our State agencies is 455 lakh tonnes. But there is a CAP. CAP is also a scientific coverage. All over the world, not only in India; I have gone to China; there also, a large quantity of foodgrains has been stored. This is also CAP. So, it is more covered. And CAP. We have got now 627.36 lakh tonnes to which we have added another 30 lakh tonnes. That is what I said. We are going to add more. What we have been suggesting to the States, which procure wheat specially, is that please have scientific CAP coverage. This is the instruction we are giving to the States. Sir, again, there was a question about the jute bags, which I have explained. Sir, after discussing with the Leader of the Opposition, we have formulated a programme of supply of jute bags to every State. Sir, I have got the scheme. In Madhya Pradesh, the opening stock was 30,000; indent placed was 2,69,000; inspected – 2,48,000; backlog -21,000; dispatched till date - 2,24,000;

[PROF. K.V. THOMAS]

inspection awaiting–another 24,000; balance quantity to be dispatched — 44,000, and by 18th of May, our plan is that the entire quantity will be given to Madhya Pradesh. This is the plan; that we have worked out. Similarly, Sir, in Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Bihar, all these things are being worked out. We have worked out a scheme. The State Governments cannot blame us, because in November, 2011, they should have projected their demands. They could not do it. But, still, we are trying to help them.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Okay. ...*(Interruptions)*... Now, Special Mentions admitted for today.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) in the Chair]

श्री शान्ता कुमार: आपको 6 महीने का अनाज देने पर क्या ऐतराज है? आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यह हम बार-बार पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**... सर, भारत सरकार के करप्ट ऑर्गनाइजेशंस में एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। आप उसके आंकड़ों पर पूरा भरोसा मत कीजिए।

श्रीमती माया सिंह: सर, मंत्री जी आश्वासन दें कि ...**(व्यवधान)**... चूंकि जूट बैग्स, उस अनुपात में उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या पॉलीथीन के बैग्स हैं ...**(व्यवधान)**... आप उनमें अनाज रखे जाने की इजाज़त देंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Special Mentions. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister, do you want to reply now? ...*(Interruptions)*...

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I have answered almost all the questions. But whatever other suggestions are there, I cannot give an immediate answer to them. So, with regard to the other questions which are relevant, which can be practical, I will look into them and answer them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Thank you. Now, Special Mentions.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, यह तय किया गया था कि सदन साढ़े 5 बजे तक चलेगा ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): It was only with your consensus. This is because the individual Members like to read it.

श्री थावर चन्द गहलोत: हम मना नहीं कर रहे हैं, पर रिकॉर्ड में है कि साढ़े 5 बजे तक कार्यवाही चलेगी और अब साढ़े 6 बजे गए हैं। इसलिए हाऊस की permission ली जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Whether the House feels that we should complete the Special Mentions.

DR. K.P. RAMALINGAM: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Till the last Special Mention is over, we will continue.

SPECIAL MENTIONS

Need to make strict laws to maintain permitted quantity of salts, etc in junk food by various food companies in the country

डा. राम प्रकाश (हरियाणा): महोदय, आज महानगरों के व्यस्त जीवन ने जंक फूड को हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना दिया है। हम इसके माध्यम से, अपने आपको आधुनिक दिखाने के चक्कर में, ऐसी आदतों का शिकार हो रहे हैं, जो अंततः हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रही हैं। इसमें टेलीविजन तथा अन्य संचार माध्यम भी जंक फूड को छोटे-छोटे शहरों में घर-घर तक पहुंचा रहे हैं, जिससे यहां के बच्चों में भी जंक फूड की ललक पैदा हो रही है। माता-पिता भी समय को बचाने हेतु इस जंक फूड को अपने बच्चों को देने में परहेज नहीं करते, मगर वे शायद यह नहीं जानते कि जिस जंक फूड को वे अपने प्यारे-प्यारे बच्चों को खिला रहे हैं या स्वयं खा रहे हैं, उसमें लवण आदि की मात्रा सेहत के लिए घातक है। महोदय, जो मात्रा पैकिंग पर लिखी जाती है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें उपलब्ध होती है। कमजोर कानून के कारण ये जंक फूड बनाने वाली कम्पनियां कानूनी कार्यवाही से बच जाती हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जंक फूड पर पैकिंग पर लिखी मात्रा से अधिक लवण आदि की मात्रा पाए जाने पर इन कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु कानून बनाए।

Need to check crimes against mentally-ill women and take steps for their rehabilitation

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Sir, my Special Mention is about the crimes against mentally-challenged women.

Sir, I would like to use this opportunity to bring to the notice of this august House the very grave matter about human rights violation. Crimes against mentally-ill women are on the rise, not only in India but globally also. We must ensure that those responsible for such abusive behaviour are brought to book.